सरकार के विचाराधीन है और जहां-जहां पर यह एक्टीविटीज हो रही हैं, वह सारी सरकार के ध्यान में हैं। वहां जो एक्शन लेना जरूरी है उसको जरूर उठाएंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): We now take up the legislative business. .Statutory Resolution and The Protection of Human Rights Bill, 1993, will be taken up together.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPAROVAL OF THE RIGHTS ORDINANCES, 1993

II. THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS BILL, 1993

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर, 1993 को प्रख्यापित मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 30) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का सिद्धांत रूप से हम स्वागत करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से गत अनेक वर्षों से यह विषय देश के सामने रखा गया कि देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन होना चाहिए और देश के अंतर्गत जहां भी मानव के अधिकारों का हनन होता है, उसको ठीक और कानूनी तरीका मिलना चाहिए। इसलिए हमने हमेशा यह मत रखा कि तुष्टीकरण की राजनीति से कोई अल्पसंख्यक आयोग बनाने के स्थान पर अगर हम सभी वर्गों, समुदायों, धर्मों के नागरिकों की अपने अधिकारों के हनन के बारे में जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को देखने के लिए एक मानव अधिकार आयोग का गठन करें तो उचित होगा।

महोदय, सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो शायद तुष्टीकरण के लिए कर लिया लेकिन उसके पश्चात भी सरकार ने यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रस्ताव किया है, इसका मैं सिद्धांत रूप में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो एक बहुत पुरानी मांग रही है, उसको आज एक प्रकार से स्वीकृति मिल रही है। इसका हमें आनंद है।

महोदय, दोनों सदनों में जब चर्चा होती है और खासकर लोकसभा से जब एक विधेयक पारित होकर हमारे सदन में आता है तो हमारे मन के प्रश्नों के संबंध में गृह मंत्री क्या उत्तर देंगे, इस संभावना का प्रश्नकर्ता को पता रहता है और शायद इसी पद्धति में गृह मंत्री को भी पूछे जाने वाले प्रश्नों का पता होता है। इसलिए मैं प्रश्न पूछने से पहले विनम्रता से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे सदन में उन्होंने जो उत्तर दिया है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ-साथ अगर इस सदन में कुछ मुद्दे आग्रह से रखे गए हों तो उस पर अगर समय हो तो वे पुनर्विचार करें अन्यथा दोनों सदनों की आवश्यकताओं पर एक प्रकार से प्रश्नचिह्न लग जाएगा।

हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का स्वागत किया है पर फिर भी इस गठन की पद्धति पर हमारी आपत्ति है। आपको याद होगा कि मानव अधिकार आयोग का एक विधेयक 14 मई, 1993 में संसद में प्रस्तुत हुआ था। यद्यपि उस विधेयक और वर्तमान विधेयक में जमीन-आसमान का अंतर है, यद्यपि उस विधेयक में जो त्रुटियां थीं उनको कुछ न कुछ कम करने का प्रयास इस विधेयक में जरूर किया गया है लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि पहले तो विधेयक संसद में आया। संसद में आने के बाद गृह मंत्रालय की जो स्थायी समिति बनी है, नई पद्धति के अनुसार उसके पास यह विधेयक चला गया। वह समिति इस पर विचार कर रही थी और 6 दिसंबर को उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रख दी। मैं भी उस स्थायी समिति का सदस्य हूं इसलिए 9 महीने से मैं उसकी प्रक्रिया का नज़दीक से अध्ययन कर रहा हूं।

उस प्रक्रिया के बाद में यह कह सकता हूं कि यद्यपि इस समिति के मन में जो था वह इस विधेयक के तन में है, लेकिन समिति का सदन के सामने रिपोर्ट आने के पहले ही गृह मंत्रालय में, समिति के मन में या रिपोर्ट में क्या हो सकता है, इस का अंदाज़ लेकर किस प्रक्रिया से यह पूर्ण करके यह विधेयक लाया है, इसकी मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवहार में जब समिति इस पर विचार कर रही थी, समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी थी तो 28 सितंबर को अचानक सरकार को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी? जैसे मैंने कहा कि इस पर गृह मंत्री का मन मैं पढ़ सकता हूं और उस पढ़ने में स्थिति यह है कि गृह मंत्रालय का कहना, लगता यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत में मानव अधिकारों के हनन के संबंध में चर्चा होने की संभावना थी और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में यह चर्चा

[श्री प्रमोद महाजन]

होती और उस चर्चा के पश्चात अगर हम कोई कानून बनाते तो शायद दुनिया यह मानती कि कानून इनके मन में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा के बाद इनके मन में कानून आया और इसलिए बनाया और इसलिए आलोचना के बाद कानून बनाने से तो अच्छा होता कि आलोचना के पहले हम कानून बनाते। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाली संभाव्य चर्चा में, होने वाली संभाव्य आलोचना को निरस्त करने के लिए अचानक अध्यादेश लाने का निर्णय सरकार ने लिया, ऐसा सरकार का उत्तर हो सकता है। जब वह उत्तर न हो तो मैं समझ नहीं सकता कि क्या हो सकता है...

सदन के नेता (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण): प्रेसीडिंग्ज पढ़ लीजिए, मालूम हो जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन: तो इसलिए प्रश्न मेरे मन में यह आता है कि अगर सरकार का यह उत्तर है तो इस उत्तर से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि एक तो मानव अधिकार आयोग गठन के संबंध में मई में विधेयक लाया गया, तब संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा नहीं हो रही थी, हमारी स्थायी समिति के पास चला गया तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा नहीं हो रही थी, इसलिए यदि सरकार के मन में मानव अधिकारों के संबंध में आयोग गठन का इरादा पहले ही स्पष्ट हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संभावित चर्चा से डरकर उसकी चिन्ता करते हुए उसके पहले ही अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो चर्चा हो, आलोचना हो, मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्र उस आलोचना को देखे नहीं, हम उसकी चिन्ता न करें, हम विश्व मत की चिन्ता जरूर करें, किसी भी सरकार को सरकार चलाने के लिए विश्व मत की चिन्ता करनी पड़ती है इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन विश्व मत की चिन्ता करना बात अलग है और विश्व मत के दबाव में एक खास निर्णय आगे पीछे करना यह दूसरी बात है। इसलिए छोटे से विश्व में हम विश्व में बातचीत करके निर्णय ले सकते है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा के डर से अगर यह पहले विधेयक आया होगा, पहले अध्यादेश जारी हुआ होगा तो मुझे लगता है यह गलत प्रक्रिया है। फिर उसका मैं यह अर्थ निकालूं तो मेरी गलती नहीं होगी कि सरकार को मानव अधिकारों के अधिकारों का जो हनन देश में होता है उसकी चिन्ता कम है, हमारे हनन के संबंध में विदेशी नागरिक क्या सोचते है शायद इसकी चिन्ता ज्यादा है, इसलिए इस मानव अधिकार आयोग के गठन के पीछे अगर मन से सरकार का इरादा मानव के अधिकारों के हनन को रोक लगाना है तो शायद गठन का उपयोग हो सकता है अगर केवल संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा को रोक लगाना है तो मुझे लगता है कि आयोग आगे जाकर निरर्थक साबित हो सकता है क्योंकि कोई भी एक नई संस्था निर्माण करने के पहले, उस संस्था की निर्मिति के लिए हमारे मन का इरादा, नीति बाद में आएगी, हमारी नीयत के बारे में स्पष्टता, पारदर्शकता आवश्यक है और जिस प्रकार अध्यादेश लाया गया उस अध्यादेश लाने के तरीके से यह लगता है कि सरकार की नीयत में वो स्पष्टता, पारदर्शकता नहीं है जो इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर होनी चाहिए थी। वह विश्व मत के दबाव में, मुझे पता नहीं किसका क्या दबाव हो, लेकिन कम से कम जो उत्तर से मुझे दिखा है कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा का दबाव तो सरकार ने मान ही लिया है, शायद न माने हुए अनेक दबाव भी उसमें हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस की पद्धति पर ही मुझे आपत्ति है। अच्छा होता कि हम अपने मन से अधिकारों का हनन न हो इसलिए आयोग का गठन करते।

दुनिया को इस बात में हम को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा मैंने शुरू में कहा पहले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग कर रही है। अगर सुनना ही था तो संयुक्त राष्ट्र संघ को सुनने की जगह आप गलती से भारतीय जनता पार्टी को सुन लेते तो कम से कम देश के अंदर आयोग का गठन हो जाता। आयोग की जो सफलता है वह सफलता आयोग के गठन पर निर्भर है। अगर आयोग का गठन ठीक हो तो आयोग सफल हो सकता है। अगर गठन में ही किसी प्रकार की गलती हो तो वह सफल नहीं हो सकता। अब आयोग के गठन के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति में जो महानुभाव हैं, व्यक्तिगत उनके रूप में या उनके पदों के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता हैं, लोक सभा अध्यक्ष हैं और उपसभापति हैं। इसलिए मुझे लगता है पद से भी श्रेष्ठ हैं और व्यक्ति के रूप में भी मुझे इन पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक विधेयक का संबंध है इसमें पद ही लिखा है, व्यक्तियों से इसका कोई संबंध नहीं है। एक क्षण इतना ही मुझे लगा कि क्या लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति को इस प्रक्रिया में लेंगे। क्योंकि इस आयोग के गठन पर आगे कभी चर्चा हो तो जो आयोग के व्यक्ति निर्धारित हों उसमें इनका लाना कितना उचित है इसके लिए मन में थोड़ा सा सन्देह है, इन पदों के बारे में नहीं, या पदों पर बैठे व्यक्तियों के बारे में नहीं। लेकिन अगर हम संसद को इस प्रक्रिया से,

जैसे लोक सभा का अध्यक्ष है लेकिन राज्य सभा का अध्यक्ष नहीं है, राज्य सभा का उपसभापति है, शायद इसका कारण यह हो सकता है कि राज्य सभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति को हम किसी गठन में इस प्रकार से लें तो शायद यह सरकार को उचित नहीं लगा हो, यह मेरा अंदाज है, अगर अंदाज ठीक है तो मुझे लगता है इसी प्रक्रिया में लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा का उपसभापति दोनों को उससे थोड़ा अलग रखते तो शायद उपयुक्त होता।

इसमें उच्चतम न्यायलय के न्यायमूर्ति की भूमिका के संबंध में एक चर्चा इस देश में चली है। न्यायालय में कोई न्यायमूर्ति अगर पद पर आसीन हो तो उसको नियुक्त करने के पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुमति लें और उनसे बातचीत करके तय करें, इस प्रकार का प्रावधान इसमें है। वह ठीक भी है और आवश्यक भी। क्योंकि न्यायूमर्ति उनके नीचे काम कर रहा है तो आप उनको वहां से उठाने के पहले स्वाभाविक रूप से मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे ही। लेकिन क्या मुख्य न्यायाधीश को इस समिति का अंग बनाया जा सकता था? इसमें सरकार का जिस प्रकार का उत्तर है, सरकार का जिस प्रकार का कहना है उससे लगता है और मन में शंका है कि जैसे 6 पदों का संबंध है शायद सातवां पद उसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो। लेकिन शायद मुख्य न्यायाधीश के मन में किसी न किसी प्रकार की इसमें आशंका थी, वह इस को ठीक नहीं मानते थे और शायद सरकार के सम्पर्क करने के बाद उन्होंने अपना मन इस पक्ष में नहीं दिया। इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से जानना चाहता हूं...

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी): आप कितना समय और लेना पसन्द करेंगे?

श्री प्रमोद महाजन: 5-7 मिनट। मैं इसलिए जानना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के मन में ऐसी कौन सी आशंकाएं थी जिसके कारण वे इस समिति पर नहीं आये और क्या ऐसी आशंकाएं थी जिस को दूर करना लगभग असंभव था? इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सारी प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के मान में चाहे संदेह किसी प्रकार के हों लेकिन यही सरकार के उत्तर से पता चलता है तो मुझे लगता है इन सन्देहों का निराकरण होना आवश्यक है अन्यथा जब सदन पर एक बात कही जाती है तो दुनिया the Chief Justice of India had some reservations. मुझे लगता है रिजर्वेशन शब्द ऐसा है कि इससे इतने अर्थ निकाले जायेंगे कि उनका गठन क संबंध में था, व्यक्तिगत रूप में था, नामों के संबंध में था, कानून के संबंध में था, प्रक्रिया के संबंध में था, इसकी आवश्यकता के संबंध में था, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह था लेकिन उसका निरकारण सदन के समाने होना यह राष्ट्र की दृष्टि से आवश्यक है इसलिए मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा..।

मैं गृह मंत्री जी से यह प्रार्थना करुंगा कि वे इस शंका का भी निराकरण करें। इसमें तीसरा मुद्दा है और जो लोगों के सामने रखा गया है और उस पर बहस भी हुई है कि मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो संगठन है उनकी आपत्ति है कि जो नियुक्ति करने वाली समिति है इसमें हम कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति रखते जो व्यक्ति इन कार्यों से संबंधित होते, जो व्यक्ति कानून की प्रक्रिया से संबंधित होते तो शायद आयोग के गठन की निष्पक्षता के संबंध में अच्छी राय लोगों की बन सकती थी। न्यायमूर्ति और गैर-सरकारी जो लोग इससे जुड़े हुए है, आयोग के गठन की निर्मिति की प्रक्रिया में उनका सहयोग लिया जा सकता था। इस संबंध में भी अगर निराकरण हो जाय तो अच्छा होगा।

किसी भी आयोग की सफलता का दूसरा मापदण्ड है उसकी परिमाणिकता। मुझे ऐसा लगता है कि मानव अधिकारों का जो उल्लंघन होता है, यह मानव अधिकारों का उल्लंघन एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अपने देश में कानून के इतने प्रावधान है कि उसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है उसमें न्याय मांगने की तुलनात्मक अधिक सुविधा उपलब्ध है। समस्या तब आती है जब सरकार या पुलिस मानव के अधिकारों का उल्लंघन करती है। जब मैं सरकार और पुलिस कह रहा हूं कि तो मेरा इसमें इरादा जम्मू-कश्मीर की तरफ नहीं है। मैं पूरे देश की स्थिति के संबंध में बात कर रहा हूं। आज हमने अनगिनत बार देखा है कि शाम ढलने के बाद कोई महिला पुलिस स्टेशन जा नहीं सकती है। हमने अनगिनत बार देखा है कि पुलिस चाहे जिसको भी उठाकर बंद कर देती है। हमने अनगिनत बार देखा है कि जेलों में ऐसे हजारों हजार लोग ठूंसे गये हैं जिनको सालों साल वहां पड़े रहना पड़ता है, उनके संबंध में कोई निर्णय नहीं होता है और न उनको सजा होती है। इसलिए जब राजा ही अत्याचारी बन जाता है या राजा का जो भी सैनिक है वह

[श्री प्रमोद महाजन]

अत्याचारी बन जाय तो मानव अधिकारों का जो उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा करना सबसे कठिन काम होता है और मुझे लगता है कि यह मानव अधिकार आयोग गठन का हमारी निर्मिति का कारण ही यह है कि अगर मुझ पर सरकार का अन्याय हो या राजा अत्याचार करे तो उसके विरोध में मुझे कहीं न कहीं स्थान होना चाहिए। यह आयोग वह स्थान है तो मुझे लगता है कि इस आयोग की परिमाणिकता जब तक निर्मित नहीं होगी जब तक आयोग के पास ऐसी व्यवस्था न हो जिसमें वह इन विषयों की जांच करे। एक पुलिस कांस्टेबल ने अत्याचार किया और अगर हम दूसरे पुलिस कांस्टेबल से पूछेंगे कि अत्याचार पर अपनी रिपोर्ट दे तो मुझे लगता है कि आयोग के पास इस प्रकार का ठीक निर्णय करनी व्यवस्था नहीं है। इसलिए कोई कहे कि इस विधेयक में कमी क्या है तो मैं यह कहूंगा कि यह आयोग ऐसा बना है जिसको दांत नहीं दिये गये हैं। वह बोल तो सकता है, लेकिन काट नहीं सकता है। और इसलिए अगर आयोग के पास जांच के अधिकार नहीं हैं तो यह इसमें कमी है। दूसरी कमी यह है कि यह आयोग एक वर्ष के भीतर ही जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है उसकी चर्चा कर सकता है लेकिन अगर 366 दिन तक का अत्याचार हो तो उसकी चर्चा नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि एक वर्ष हो या तीन वर्ष हो या दस वर्ष हों, कोई तो समय तय करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी ने दूसरे सदन में यह प्रश्न किया कि मैं तीन वर्ष करुंगा तो कल को कोई कहेगा कि पांच वर्ष क्यों नहीं करते हैं और पांच वर्ष करूंगा तो आप कहेंगे कि दस वर्ष क्यों नहीं करते है। मैं गृह मंत्री जी से उसी हिसाब से प्रश्न पूछता हूं कि यह एक साल क्यों किया, नौ महीने क्यों नहीं किया? नौ महीने करते तो छः महीने क्यों नहीं किया, तीन महीने क्यों नहीं करते, आठ दिन क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि इस बात से तो मैं सहमत हूं कि आखिर 35 अंक पर एक आदमी इम्तहान में पास हो जाता है और 34 अंक पर पास नहीं होता है। क्यों? इस क्यों का कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं है। वास्तव में इस मानव अधिकार आयोग का गठन ही समझ में नहीं आया है।

उस गरीब आदमी को उसका गठन समझ आये, फिर उस पर अत्याचार हो, फिर अत्याचार के बाद आपके पास आने का प्रयास करे, मुझे लगता है कि इसमें एक वर्ष तो अत्याचार को प्रकाश में आने में लगता है यह देश इतना बड़ा है कि दूरदराज के इलाकों में आदिवासियों पर, दलितों पर जो अत्याचार ग्रामीण इलाकों में होंगे तो उन ग्रामीण इलाकों के आदिवासियों, गरीबों और दलितों पर हुए अत्याचार दिल्ली में मानव अधिकार आयोग के गठन या प्रदेश मानव अधिकार आयोग के गठन तक, इसमें इतना समय लगेगा कि शायद एक साल के समय में वह खत्म हो जायेगा और इस प्रकार उसका गठन तो होगा लेकिन उसका निराकरण नहीं होगा। इसलिए गृह मंत्री जी से मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कम से कम राज्य सभा में अपने उत्तर में भले ही इसमें बदल करें या न करें राज्य सभा में मुझे याद है पहले कि आप 47 से बाद के कितने भी सवाल पूछ सकते थे। लेकिन फिर राज्य सभा के सेक्रेटेरिएट ने कहा कि 47 से कहां से आंकड़े लेकर बैठेंगे उसको तीन साल कर दिया। You can go back to three years. अब तीन साल के पूछे जा सकते हैं। इससे पीछे के बारे में आपको पूछने हों तो आप पूछ नहीं सकते। आप भी राज्यसभा के सदस्य है, बहस भी राज्यसभा में चल रही है। मेरी प्रार्थना यह होगी कि कम से कम इस एक वर्ष को अगर आप तीन वर्ष कर दें तो मुझे लगता है कि आपकी जो नीयत है कि मानव-अधिकारों के हनन के निराकरण का प्रयास हो, इससे उस नीयत पर भी संदेह नहीं होगा और आपका जो उद्देश्य है वह भी पूरा हो जायेगा। इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि आप प्रेस्टिज का इश्यू मत बनाइये, क्योंकि यह बन चुका है कि मैं एक ही साल रखूंगा। मैं यह नहीं कहता कि आप इसे 5,10 या 15 साल करिये लेकिन कम से कम तीन वर्ष का समय इसका रखिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि कानून जो देश के लिये बनायेंगे उसमे इसका उपयोग हो सकता है।

महोदय, इसमें केंद्र ने सेना को पूर्ण रूप से दूर नहीं रखा है। लेकिन अधिकांश रूप से उसे इससे दूर रखा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जम्मू और कश्मीर में सेना को ही मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मानते हैं। मैं जरूर यह मानता हूं कि जहां तक कश्मीर की समस्या का प्रश्न है वहां और अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी और उग्रवादी शस्त्र लेकर आयेंगे तो सेना वहां बड़ी कठिन स्थिति में काम कर रही है और ऐसी कठिन स्थिति में हिन्दुस्तान की सेना अगर कश्मीर में हमारी स्वतन्त्रता को बनाये रखने का प्रयास कर रही है तो मुझे लगता है कि सदन में इस प्रकार की चर्चा जिससे सेना का मनोबल गिरे, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं मानता हूं कि टैरेरिस्ट अगर किसी को मारे तो उससे मानव अधिकारों का हनन नहीं होता लेकिन अगर टैरेरिस्ट या उग्रवादियों को पकड़ने के लिये सेना की ओर से गोली चले तो वह मानव अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। यह विदेशी मान

सकते हैं यह हमारे यहां सूडो-ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वे मान सकते है कि लेकिन में ऐसा नहीं मान सकता हूं। (समय की घंटी) थोड़े समय में खत्म करता हूं।

देश की जरूर यह रुचि है कि सेना ठीक ढंग से काम करे। लेकिन इसके साथ साथ हम यह न भूलें कि सेना हो या पुलिस, हम सब व्यक्ति होते है, हम से गलती होने की संभावना होती है और सेना की कश्मीर में लड़ाई की प्रशंसा करते समय भी वे गलती कर सकते है और यह अगर हमारे मुंह से निकल जाय तो इसमें भी निरंकुशता बढ़ सकती है। इसलिए सेना की आज की लड़ाई की स्थिति का अध्ययन करते हुए उनके साथ पूरी सहानुभूति और समर्थन रखते हुए मेरा यह कहना है कि कहीं न कहीं हमको यह व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हमारे ही बनाये नियमों से गलती से एक जगह भी मानव अधिकारों का उल्लंघन करे तो इसमें थोड़ी सी जो व्यवस्था बनी है, उसमें जो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है उसको वह ठीक से निभाये।

अब में केवल दो छोटे मुद्दे कहकर अपना विषय समाप्त कर रहा हूं इस आयोग का जो मुख्य रूप है वह सिफारिश के रूप में है। It is a recommendatory body. अब सिफारिश में दो स्थितियां हैं। इसे किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का तो छोड़ दीजिये इसे किसी को राहत देने का भी अधिकार नहीं है। किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया तो उसको कुछ न कुछ राहत दो इसका भी अधिकार इसे नहीं है। जो संस्था न राहत दे सके, न दंडित कर सके, केवल सिफारिश करे तो मुझे लगता है कि उस संस्था की शक्ति भी कम हो जाती है। उस संस्था में लोगों की रुचि संस्था को चलाने वालों की रुचि भी कम हो जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि दो साल मेहनत करने के बाद जो सिफारिश हम करेंगे, उन सिफारिशों पर अगर बाद में सरकार अमल न करे, उनमें से कुछ सिफारिशों को उठाकर फेंक दे, हमने जो राहत देने की बात की उसको अगर सरकार न माने तो फिर काम करने वाले वाला या न्याय मांगने वाले दोनों की रुचि समाप्त होगी।

जैसे मैंने कहा कि मैं जानता हूं गृह मंत्री जी की मंशा है। उन्होंने दूसरे सदन में यह कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशें भी रिकमेंडेटरी हुआ करती है, वह निर्णय नहीं लेता है लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशें कभी सरकार ठुकराती नहीं है। अब इस वाक्य का मे केवल स्पष्टीकरण के रूप में क्या यह अर्थ लूं कि मानव अधिकार आयोग की जो भी सिफारिशें होगी वह कानून में भले ही ठुकराने का अधिकार सरकार को हो लेकिन सरकार यह भरसक प्रयास करेगी कि जितनी भी उनकी सिफारिशें होंगी जैसे वित्त आयोग की सिफारिशें मान लेते हैं क्या गृह मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस आयोग की सिफारिशें भी उसी प्रकार से मान लेंगे जैसे हम वित्त आयोग की मान लेते है। उसमें भी मैं एक बात और कहूं। दंड देने का जो निर्णय है उस पर शायद दो मत हो जाएं कम से कम राहत देने की जो सिफारिश आ जाए उस सिफारिश को पूर्ण रूप में माने का आश्वासन अगर गृह मंत्री जी दे तो मुझे लगता है कि इसकी अधिक सार्थकता होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक छोटा मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं इसमें राज्यों के भी मानव अधिकार आयोग के गठन की चर्चा है। अब इसमें मुझे कभी कभी इस बात का सन्देह होता है कि केन्द्र में भी एक मानव अधिकार आयोग होगा और राज्य में भी होगा, मैं केन्द्र और राज्य के संबंधों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम के कम केन्द्र और राज्य के मानव अधिकार आयोग जो होंगे उनके आपस में क्या रिश्ते होंगे, वह किस किस बात पर विचार करेंगे या दोनों आयोग एक ही बात पर विचार करके दो अलग निर्णय लेंगे जिसकी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, अगर केन्द्र और राज्यों के दो आयोग एक ही बात पर विचार करें दो निर्णय ले ले तो फिर दो निर्णयों की स्थिति केन्द्र और राज्य सरकार की स्थिति क्या बन जाएगी? क्या गृह मंत्री जी ने इस संभावना का भी विचार किया है और अगर ऐसी संभावना हो तो गृह मंत्री जी इस संभावना को भविष्य में कैसे देखते है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण के अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि मानव अधिकार आयोग के गठन की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर और पंजाब के संबंध में हुई है। मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान में इतने कानून बने हुए है और उन कानूनों के अन्तर्गत पुलिस को इतने अधिकार दिये गये है कि उनके खिलाफ सामान्य व्यक्ति तो क्या संसद् सदस्य भी नहीं लड़ सकता। मैंने जब अपना राजनीतिक जीवन प्रारम्भ किया तो मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ने आया। मैंने उसको कहा कि मुझे कौन से कानून में पकड़ रहे हो। उसने कहा कि बच्चे मेरे पास बम्बई पुलिस एक्ट में इतने कानून हैं, उनमें से अगर मैं दो चार भी उपयोग में ला दूं तो तेरा चलना-फिरना भी बंद कर दूं तू मुझे सिखाने-पढ़ाने की कोशिश मत कर। मुझे लगता है कि राज्य के पास, पुलिस के पास इतने भयानक अधिकार हैं

[श्री प्रमोद महाजन]

कि अगर एक इंस्पेक्टर उस अधिकार का उपयोग करना चाहे तो गृह मंत्री जी को भी परेशान कर देगा, अगर वह तबादले से न डरता हो तो फिर बड़े से बड़े मंत्री को भी वह सिखा सकता है। इतने अधिकार उसके पास हैं कि उसके दुरुपयोग के विरोध में हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आयोग के पास यह काम है कि वह इन सारे कानूनों की समीक्षा करे, गृह मंत्रालय इस काम में आयोग की ज्यादा मदद करे। आज यह जो सारे कानून बने हैं छोटे से लेकर टेरोरिस्ट एक्ट तक जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को जेल में ठूंसने का अधिकार पुलिस को है, अगर इस कानून की समीक्षा को जाए और इस आयोग के पास जितना कम काम जाए उतना ही अच्छा है। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार की सफलता तब होगी जब आयोग के पास कोई काम नहीं होगा। अगर आयोग के पास बहुत काम चले जाएंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि गृह मंत्रालय बहुत अत्याचार कर रहा है। इस आयोग के पास एक भी शिकायत न जाए, यह आयोग की सफलता का मापदंड बनाना है तो उसके लिए कानून में आमूल-चूल परिवर्तन करने की व्यवस्था का जिसमें थोड़ा सा उल्लेख है, उस पर अधिक विचार करना चाहिये, यह प्रार्थना मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Mr. Vice Chairman, Sir, I move:

That the Bill to provide for the constitution of a National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions in States and Human Rights Courts for better protection of human rights and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. It would be recalled that a Chief Minister's Conference on Human Rights was convened in September, 1992, which had, among other issues, welcomed and endorsed the proposal to establish a National Human Rights Commission. We in India have a strong and elaborate Constitutional legal framework for the protection and promotion of the rights of the individual in their widest form. We have a strong independent judiciary which has all along acted to protect the rights, liberty and dignity of the individual. Special provisions have also been made in the law and institutions established for taking measures and protect the rights and strengthen the status of the most vulnerable sections oi the society. Our dynamic democratic parliamentary system, the free and vibrant press, and a host of nongovernmental organisations together also constitute a powerful watch-dog mechanism in the system.

Despite the constitutional and legal safeguards, however, there can be weaknesses and shortcomings in the system which need to be identified and addressed on a continuing basis, and this has also been the endeavour of the Government.

Over the past few years, there has been growing concern on issues relating to human rights, the world over, and complaints of deprivations and infractions of human rights continue to be voiced in the country also. The environment in which the law enforcement agencies have to function, has also become progressively more complex, as a measure of strengthening and streamlining the system further, and bringing greater transparency and accountability into it, it was felt that we may establish a National Human Rights Commission. It is hoped that, through its multiple functions, including inquiries into specific cases, it would be able to bring about a sharper focus, and awareness about human rights; promote the better enforcement of existing safeguards; and bring in greater accountability into the whole system. At the same time, it was also considered necessary that while setting up such an institution, care -must be taken to avoid duplication with well established institutions and processes, and the essential spirit of the federal principles enshrined in the Constitution should be preserved.

Pursuant to the Chief Minister's Conference, a wide range of discussions

were held on the issue in the form of Seminars in various parts of the country, meetings with the States Governments, consultations with leaders of political parties, and in a committee set up under my Chairmanship and comprising, among others, Chief Ministers of five States cutting across party lines. After taking into account the views expressed in sueh discussion and consultations, we had drawn up a Bill for the setting up of a National Human Rights Commissions, which was introduced in the Parliament on the 14th May, 1993. This was referred by the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha to the Standing Committee of Parliament for the Ministry of Home Affairs. The officials of the Ministry had been associated by the Committee in its deliberations, which gave us an opportunity to broadly identify the major areas of concern which would need to be addressed. A large number of reactions to the Bill also appeared in the media and otherwise which also contributed to this process.

Due to certain emerging situations, it was considered necessary to speedily bring to fruition the exercise that had been commenced over a' year ago for establishing a National Human Rights Commission, and that time was of the essence. The protection of Human Rights Ordinance was, therefore, promulgated on 28th September, 1993 after incorporating substantial changes in the original Human Rights Commission Bill, 1993 which were aimed at addressing the major areas of concern that had been expressed.

The protection of Human Rights Bill, 1993 was introduced in the Lok Sabha on 9th December, 1993, to replace the ordinance by an Act of Parliament. After deliberations, it was passed by the Lok Sabha, with a few amendments, on 18th December. Without going into details about the individual provisions. I would at, this stage, merely like to say that the Standing Committee, whose reprot is before the House, observed that almost all the amendments suggested by it on the various provisions of the Bill had been incorporated in the Ordinance. This would indicate the spirit with which the Government has approached this whole issue, and the fact that sincere effort has been made to address the reservations which had been expressed in regard to this important Bill. At the same time, we realise that we are seeking to establish a new type of institution of which there is no experience in the country, and little elsewhere. Also, this is an institution which will have to co-exist with a host of others which are already concerned with different aspects . of human rights protection and promotion, and function within laid down constitutional and legal parameters. It is possible that as we learn from experience, it may 2JO0 P.M. be found necessary to bring in changes in the future. For the present, I wo"uld like to urge this august House to give its fullest consideration to the Bill so that the Ordinance already promulgated can be converted into an Act of Parliament.

With these remarks, 1 commend the Bill for the consideration of this august House.

The questions were proposed,

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, protection of human rights is a very vital aspect of our life as it involes the dignity of an individual and the nation as such. In general, Sir, therefore, I approve the spirit and content of the proposal which is intended to set-up the Human Rights Commission. But, Sir, the Human Rights Bill, as introduced in May 1993 was seriously flawed.

Whilst the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs was examining the Bill, there was a sudden burst of energy leading to the promulgation of the Protection of Human Rights Ordinance on 28th September, 1993. What were the circumstances which necessitated

Dr. Naunihal Singh

immediate action for an "Ordinance? The mystery is as inexplicable as some of its provisions.

A human rights commission to justify its *raison d'etre* should satisfy the dual test of credibility and effectiveness. And that will depend upon: (i) its composition and (ii) the extent of its powers. Unfortunately, there has been no change in the composition of the appointment Committee which will consist of the Prime Minister, the Home Minister, the Speaker, The Deputy Chairman of the Rajya Sabha and the Leaders of the Opposition in both the Houses. However, the exclusion of the non-Government organisations representatives and of the Bar is a serious omission.

Further, the effectiveness of the Commission in protecting human rights will be almost minimal for various reasons. Firstly, the Commission has not been provided with its own 'independent investigating machinery. Secondly, the period of limitation of one year from the date of the act of human rights violation Tor filing a complaint is woefully short. Thirdly, the functions of the Commission in the main, are recommendatory and hortatory. Last but not the least, the exclusion of the military and security forces etc. from the limited scrutiny of the Commission, is the final act of its emasculation.

Besides, the Commission is not being set up in response to any demand from the Indian activists campaigning for civil or democratic rights. Surprisingly, it is, in fact, being established to meet the criticism of India's human rights record by the Western-aid donors. Therefore, it is a cosmetic exercise to dispel an impression by dealing with the allegation instead of positive measures to prevent violation of human reights.

Curiously enough, section 12 of the Ordinance avoids reference to terrorist and secessionist groups whereas it should be obligatory that the Commission should also look into the violation of human rights by others in an organised manne or otherwise, as also by the secessionis groups and organisations.

Furhter, Sir, it is shocking to note thai the recommendations of the Human Rights Commission are not binding on the Government. For example, where special enquiries had established violation of human rights involving riots victims of the 1984 riots in New Delhi, in the wake of Indira Gandhi's assassination, the guilty have not been brought to book so far. In that context, the appointment of Justice Ranganath Misra as Chairperson has raised eyebrows. His arbitration on human rights issues is, to say the least, not free from controversy. The Commission of Inquiry into the 1984 riots, anti-Sikh riots, that he headed, was under attack from human rights activists for failing to nail the culprits and allowing the Government to drag its feet over the dispensation of justice to the victims.

Sir, the Report of the Madon Commission on Bhiwandi riots in 1970 has not been implemented so far. Not only that; the manner in which the Ordinance has been promulgated, without allowing for adequate debate in Parliament over controvesial provisions, makes it clear that it is merely a face-saving gesture to counter the strident anti-India chours. Therefore, the proposed Human Rights Commission by the Central Government after issuing an Ordinance is merely a hoax.

Further, the authorities concerned framed the Ordinance governing the powers, scope and constitution of the Commission in such a way that it would be toothless lion and it would end up like several other Commissions constituted by the Government from time to time. It appears that the Commission would have no jurisdiction over Chapter IV of the G3nstitution which deals with social and other rights of people.

The fact is that multinational companies backed by the western nnwr.

,and other industrial States wanted to grab the Indian market.

As such, the Governments, of such States were using arm-twisting tactics against .the Indian Government to make it agree to accept their terms regarding human rights commission etc. It is surprising that while the USA was concerned about the human rights of Kashmiris, it was silent on the rights of the peasants of Bihar and Andhra Pradesh, the Kurds, the Vietnamese and the Iraqis. In fact, the USA raises the issue of human rights when it suits it politically and economically

The Human Rights Commission proposed to be set up by the Central Government would be a meaningless body as the Government had not given it sufficient powers to deal with human rights violations; and it was all a fraud

Despite the Ordinance, it is not too late to remove the various flaws and show the Government's genuine commitment to human rights and to dispel the unavoidable impression that the proposed legislation is merely cosmetic and meant for foreign consumption.

In conclusion, Sir, it is my warning that the first Human Rights Commission of India should not be a teasing illusion. Hence, I support the statutory resolution brought in this House to disapprove the Protection of Human Rights Ordinance, 1993. Thank you, Sir.

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब): वाइस चैयरमैन साहब, मैं, इस बिल की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं पहली ह्यूमन राइट्स कांफरेंस ईरान में हुई थी और उसमें ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के चार्टर को तैयार किया गया था। उसके 25 साल बाद वियना में ह्यूमन राईट्स प्रोटेक्शन के चार्टर को अपडेट किया गया। हिंदुस्तान की सरकार हमेशा की ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन, प्रमोशन और प्रिजर्वेशन के लिए बाध्य रही है और हमारी जम्हूरियत का जो ढांचा है यह इस बात का पाबंद है। ह्यूमन राइटस और ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करना हमारे कांस्टीट्यूशन में भी है और यह हमारी तहजीब में भी शामिल है।

हिन्दुस्तान की सरकार ने ह्युमन राइटस के प्रमोशन और उसकी हिफाजत के लिए पार्लियामेंट में बिल भी लाया। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब की सदारत में एक कमेटी भी बनी, जिस कमेटी में ह्युमन रिसोर्स डवलपमेंट मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, पांच स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर शामिल थे और इस सारी चीज को वहां बहुत अच्छे तरीके से डिसकस किया गया। हमारे मुल्क में पांच बड़ी जगहों पर इस मौजू पर सेमिनार भी हुए कलकत्ता, बंबई, दिल्ली और हैदराबाद में और इस मसले को बहुत संजीदगी से डिसकस किया गया। हिन्दुस्तान की बार-कौंसिल ने भी एक सेमिनार किया, जिसमें इस सारे मुद्दे पर गहराई से डिसकस किया गया और सारे मुल्क में इस पर चर्चा हुई, वाइड रेंजिंग डिसकशन हुई। इन सब बातों की बिना पर, इन सब डिसकशन के आधार पर हिन्दुस्तान की सरकार ने एक आर्डिनेन्स ह्युमन राइटस प्रोटेक्शन कमीशन के सिलसिले में पेश किया, जिसकी रिप्लेमेंट में आज यह बिल आपके सामने है।

वाइस चेयरमेन साहब, इसकी कंपोजीशन जाहिर करती है कि गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, गवर्नमेंट इसको इफेक्टिव, और, इस पर लोगों का भरोसा हो, इस तरीके का तशकील देना चाहती है। इस कमीशन के चेयरमैन जो होंगे, वह हमारे सुप्रीम-कोर्ट के जज रह चुके हों, वह होंगे, एक मैम्बर और जो होंगे, वह भी सुप्रीमकोर्ट के जज होना लाजमी है, एक दूसरे मैम्बर किसी हाइकोर्ट के जज रह चुके हों, यह लाजमी है और दो मैम्बर ऐसे होंगे जिनको ह्युमन राइटस की वर्किंग का पूरा एक्सपीरियेन्स हो और नालेज हो।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए।]

यह बिल हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा के एक वायदे को पूरा करता है, जिसमें कि हमने वायदा किया था ऐसे ह्युमन राइटस कमीशन के बिल को हम तशकील देंगे ताकि इस सिलसिले में कोई खामी हो या कोई कमी हो तो ऐसा चाबुक होना चाहिए जो उस खामी और कमी को दूर कर सके। इस वायदे की पूर्ति के लिए इस बिल को लाया गया है। इस बिल की इफेक्टिवनेस के बारे में मेरे साथ ने जिक्र किया है, मैं हाऊस के सामने यह रखना चाहता हूं कि एक सिम्पल पिटीशन आप कमीशन के नाम लिखिए और..

It will attract the attention of the Commission and the Commission can institute an inquiry on a simple petition

श्री वीरेन्द्र कटारिया

by any citizen of this country.

इसके अलावा इफेक्टिवनेस इस बात से भी जाहिर है कि जो कोर्ट में केसेज हो उनका भी नोटिस यह कमीशन ले सकता है और उसमें इंटरवीन कर सकता है। मेरे ख्याल में यह बहुत मौजू क्लाजेज है इस बिल में, जिससे कि इसकी इफेक्टिवनेस और इसका जो प्रभाव है उस पर लोगों का एतमाद और भरोसा, मेरे ख्याल में, किया जा सकता है।

वाइस चेयरमेन साहब, मैं दो-चार सुझाव और भी रखना चाहता हूं। क्लाज-21 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऐसे कमीशन बनाने की व्यवस्था है, लेकिन यह उनकी provision for making such Commissions in the States as well as at the district levels should be made mandatory.

ताकि कोई गुंजाइश न रह जाए, जो हमारा मकसद है वह स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा पर और उनकी लाइक या डिसलाइक पर निर्भर न हो बल्कि यह कानून का तकाजा हो कि स्टेट में भी ऐसे कमीशन बनने लाजमी है और डिस्ट्रिक्ट लेबल पर भी इस तरह के कमीशन लाजमी तौर पर बनने चाहिएं।

इसके अलावा मैं यह तजवीज़ करना चाहता हूं कि कमीशन की अगर अपनी इन्वेस्टीगेशन एजेंसी न हो तो इसका मकसद पूरे ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। आउट साइड एजेंसी, जिस पर कि कमीशन का अख्तियार न हो, वह कमीशन का जो काम है, उसमें इतना एतमाद पैदा नहीं कर सकेगी। जितना कि अगर इस कमीशन की अपनी इन्वेस्टीगेशन एजेंसी हो। तो मैं यह तजवीज करता हूं कि आप इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की तजवीज़ इस कमीशन के बिल के अंदर ले आएं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान हमेशा आवाज उठाता रहा है अप्रेशन के खिलाफ। आजादी के पहले भी हिन्दुस्तान के लोगों ने अप्रेशन के खिलाफ, वह किसी फार्म में हो, किसी शक्ल, में हो, किसी मुल्क में हो, अपनी आवाज बुलंद की है और आज भी हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट उसी सारे हिस्से को अपने जो मकसद हैं, उसमें वह शामिल किये हुये है और इस बात की पाबंद है कि ह्यूमन राइट्स को हमने महफूज़ रखना है और उनकी हमने हिफाज़त करनी है। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में, वाइस चेयरमैन साहब, अर्ज करना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी आरगेनाइजेशन्स हैं जिनके ह्यूमन राइट्स के मामले में अलग-अलग मापदंड हैं। पंजाब, जिस सूबे से मैं आया हूं, 12 साल तक वहां पर मौत का नंगा नाच होता रहा। बसों से, घरों से, गाड़ियों से, खेतों से इंसानों को, औरतों को, बच्चों को चुन-चुनकर निकाला गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक-एक कातिल ने एक-एक हजार कत्ल किये, लेकिन वह नाम-निहाद ह्यूमन राइट्स जो एजेंसियां हैं, जो उनका ढिंढोरा पीटती हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और जब सारा पंजाब लहू-लुहान हो रहा था, ह्युमन राइट्स का कत्लेआम हो रहा था, किसी ने उस बात की तरफ उफ तक नहीं की, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि यह जो औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बेगुनाह इंसान मर रहे हैं, यह भी हयूमन राइट्स का वॉयलेशन है, इनके भी ह्युमन राइट्स हैं। उन नाम-निहाद इन्टरनेशनल एजेंसियों ने इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब एक-एक हजार कत्ल करने वाला आदमी मारा जाता था तो हयूमन राइट्स के नाम की दुहाई दी जाती थी कि हिंदुस्तान में हयूमन राइट्स का वॉलेशन किया जा रहा है और हिंदुस्तान में हयूमन राइट्स का कत्ल किया जा रहा है। मैं एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स से भी ऊपर मुल्क की एकता है, मूल्क की यकज़हती उससे बहुत ऊपर है। एक हयूमन राइट्स तो क्या, कई ह्यूमन राइट्स इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान किये जा सकते हैं। हम पाबंद है ह्यूमन राइट्स की हम कद्र करते हैं आला ह्यूमन क्दरों की, लेकिन जहां मुल्क की वजाहत का सवाल हो, मुल्क की एकता का सवाल हो, मुल्क के मासूम बच्चों को, औरतों को, नौजवानों को बचाने का सवाल हो, तो वहां अगर उनके हथियारों से लड़ना पड़े तो मेरे ख्याल में हमें इसमें कोई शर्म करने की, झिझकने की या लंगड़े बहाने करने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुल्क के दुश्मन हैं, उनसे उनके हथियार से ही लड़ना चाहिये, यह मेरा तकाज़ा है, यह मेरी इल्तजा है।

इन लफ्जों के साथ, जो बिल होम मिनिस्टर साहब ने इस सदन में रखा है, मैं उसकी पुरजोर ताइद करता हूं।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह जो बिल है, पिछले दिनों जो आर्डिनेंस आया था, उसको रिपील करने के लिये लाया गया है। विधेयक की मंशा अच्छी है और सरकार की मैं इसलिये तारीफ करती हूं कि देर आयद दुरूस्त आयद। लेकिन यह सही-सही दुरूस्त नहीं आया, काफी खामियां इस विधेयक में रह गई हैं। महोदय, 1948 में अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर ह्यूमन राइट्स, कमीशन के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक डिक्लेयरेशन हुआ—डिक्लेयरेशन आफ ह्यूमन राईट्स और उसमें कुछ बातें कही गई थी कि क्यों इसका डिक्लेयरेशन हुआ। आर्टिकिल-I में यह कहा गया था कि :

Article I says, "All human beings are born free and equal in their dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of love and brotherhood." They should have included sisterhood also.

Article 3 says, "Everyone has a right to life, liberty and security of person."

Article 5 says, "No one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."

Article 7 says, "All are equal before law and are entitled without any discrimination to equal protection by law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination."

महोदय, इसके बाद बारम्बार ह्यूमन राइट्स के बारे में दुनियां में चर्चाएं हुई और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बढ़ता ही गया। पिछले दिनों जून महीने में जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ और उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चाएं हुई। इससे पहले भी जिनेवा में सम्मेलन हुआ था। तो हमारे यहां हिन्दुस्तान में कश्मीर में इनसरजेंसी बढ़ी और जब पंजाब में इनसरजेंसी बढ़ी और उसके तहत जो कार्रवाईयां भारत सरकार की ओर से हुई, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में दुनियां भर में बहुत चर्चाएं होने लगी कि भारतवर्ष में ह्यूमन राइट्स का बड़ा भारी वॉयलेशन हो रहा है। तो इसमें विदेशी लोग हमारे ऊपर दबाव डालने लगे। एक संगठन है, इसका नाम है— एशिया वाच, यह न्यूयार्क बेस्ड ऑर्गनाइजेशन है। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें बड़े-बड़े शब्दों में कहा गया कि भारत की सरकार और हमारी सेनाएं, हमारी पैरा मिलेट्री फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज किस तरह से पंजाब और कश्मीर में कारनामा कर रही हैं, क्या-क्या वारदात हुई है। इस संदर्भ में एशिया वाच ने यह भी कहा कि अमेरिका ने हमें हथियारों की मद में कितने रुपए दिए, किस साल में हमारे फाइनेंसियल ईयर में कितने हथियारों की मद में खर्चा हुआ और विदेशों से कितने हथियार खरीदे, यह सब सरकार को मालूम है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि दुनियां के कई देशों में ह्यूमन राइट्स के जो वॉयलेशन हुये हैं उसके संबंध में लोग बहुत चुप हैं और इस पर जो विधेयक सरकार का लाना पड़ा इसके पीछे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (आई एम एफ) का भी यह दबाव था कि भारतवर्ष में ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन न हो और अमेरिका की सीनेट कमेटी ने कहा, उन्होंने वर्ल्ड बैंक, एशियन डवलपमेंट बैंक को और इंटरनेशनल मानिटरी फंड को कहा

"the Asian Development Bank to use their voice and vote in accordance with the United States Human Rights Law to promote improvement in human rights by the Indian Government."

उनके दबाब में, इंटरनेशनल दबाब में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी सीनेट के दबाब में यह विधेयक लाया गया है। लेकिन चाहे जिस किसी के दबाब में यह विधेयक लाया गया हो, उचित है और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस विधेयक को पहले लाना चाहिये था। लेकिन महोदय, इस विधेयक में बहुत खामियां रही है। हम लोगों ने, जब जनता दल को सरकार थी तो एक विधेयक — वूमेन कमीशन का पारित करवाया। बीस साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रिजोल्यूशन पारित हुआ था।

उसके तहत एक स्टेटस ऑफ वीमैन कमेटी बनी थी दुनियां भर में। हिंदुस्तान में भी बनी थी और उसकी रिपोर्ट आई थी 15 साल पहले लेकिन उसकी जो अनुशंसा थी कि एक वीमैन कमीशन बनाया जाए, वह कमीशन नहीं बनाया गया और जब जनता सरकार आई तो हम लोगों ने उस पर दबाव डाला वीमैन कमीशन बनाने के लिए और तब जनता सरकार ने वीमैन कमीशन बनाया। हम लोगों ने उस समय कहा था कि इस कमीशन को सशक्त बनाया जाए लेकिन वह भी एक पंगु कमीशन बनकर रह गया। मुझे भय है कि वर्तमान कमीशन की भी वही हालत न हो जाए।

महोदय, इस कमीशन के बारे में कहा गया है कि इसको कैसे बनाएंगे, कौन-कौन इसके मेंबर्स होंगे और इसका काम क्या होगा, ये सब बातें इसमें विस्तार से कही गई है लेकिन कमीशन को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वह अधिकार मिला नहीं। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि इस कमीशन के गठन में यह दिया गया है कि इसमें माईनोरिटी कमीशन के चेयरमैन होंगे

[श्रीमती कमला सिन्हा]

और एस०सी०/एस०टी० कमीशन के चयरमैन इसके मेंबर होंगे। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह अपीजमेंट की पालिसी है और माईनोरिटी कमीशन का आदमी इसमें नहीं होना चाहिए, मैं इसकी विरोधी हूं। यह गलत बात उन्होंने कही है क्योंकि माइनोरिटी इस देश की एक हकीकत है लगभग 16 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़ लोग माइनोरिटी के तहत आते हैं जिसमें केवल मुस्लिम माईनोरिटी नहीं है, दूसरे भी लोग हैं। इसलिए इस तरह की बात कहना अनुचित है। इसी तरह एस० सी० और एस०टी० के लोगों की संख्या भी हमारे देश में बहुत है और यह कमीशन बनने के बाद भी इन पर होने वाले अत्याचारों में कोई कमी नहीं हुई है।

मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इस देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बैकवर्ड कम्युनिटी है इसलिए उनका कोई रिप्रैजेंटेटिव भी इस कमीशन में होना चाहिए। उनका कोई रिप्रैजेंटेटिव इस कमीशन में नहीं है। माईनोरिटी कमीशन के चेयरमैन और एस०सी०/एस०टी० कमीशन के चेयरमैन इसके मेंबर होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब मेंबर्स का चुनाव हो तो एक ओ०बी०सी० का मेंबर भी इसमें रखा जाए ताकि उनकी मन में यह भावना न हो कि हमारे प्रति ह्यूमन राईट्स कमीशन उदासीन है।

महोदय, सच पूछिए तो अत्याचार किनके ऊपर होता है—जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, अत्याचार तो उन्हीं के ऊपर होता है और इनका कोई सदस्य अगर इस कमीशन का मेंबर नहीं होगा तो उनको यह भरोसा कैसे होगा कि हमें सचमुच में न्याय मिलेगा। महोदय, सबसे बड़े अन्याय का सामना किनको करना पड़ता है? इस देश की आधी आबादी औरतों की है और औरतों को जितना अन्याय का सामना करना पड़ता है, वह शायद किसी को नहीं करना पड़ता है।

महोदय, यह दुनिया का इतिहास रहा है कि जब कभी ऑकुपाईड आर्मी किसी देश में दखल करती थी या ईमरजेंसी कहीं पर होती थी तो सबसे वल्नरेबल सैक्शन ऑफ दि सोसायटी यानी वीमैन पर अत्याचार होता था। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब भारत सरकार इस विधेयक के लिए रूल्स बनाए तो उसमें ह्यूमन राईट्स ऑफ वीमैन का भी एक चैप्टर जोड़े और उसमें elimination of violence against women in public and private life, including all forms of sexual harassment, exploitation and trafficking of women, the elimination of gender bias in the administration of justice and violation of human rights of women.

इनको जरूर उसमें जोड़ा जाएं एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि आखिरकार कोई हथियार क्यों उठाता है, इमरजेंसी क्यों होती है, टैररिज्म क्यों बढ़ता है, कोई अपराध क्यों करता है? कोई जन्म से अपराधी नहीं होता है।

कोई जन्म से इनसरजेंट बनकर नहीं आता। समाज की जो व्यवस्था है, वर्तमान समाज जिस आर्थिक ढांचें पर बना हुआ है वह समाज लोगों को मजबूर करता है कि कोई जो संगठित प्रभुसत्ता है उसके खिलाफ हथियार उठाए। यह संगठित प्रभुसत्ता जो हमारे देश में भी बनी हुई है, यह ठीक है कि हमारे संविधान में दी गई व्यवस्थाएं ठीक हैं, बहुत ही अच्छी हैं, इसमें हमने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, लेकिन जो समाज की संरचना है, जो आर्थिक ढांचा है हमारे देश का, उसमें सौ में से पचास फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। लोग अशिक्षा से पीड़ित हैं। लोग अनाइम्प्लायमेंट से, बेकारी से पीड़ित हैं जिस को सरकार अपनी आर्थिक नीति के जरिए बढ़ावा दे रही है। यह स्थिति अगर रहेगी तो इस देश में इमरजेंसी घर घर में फैलेगी। आप कितने ही टाडा को लगा लें, इस को रोक नहीं पाएंगे और घर घर में लोगों को जीने के लिए हथियार ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर कोई उपाय नहीं होगा। आज के दिन जो भी काम करने जाती है महिलाओं का एक संगठन है, आंगनबाड़ी में लोग काम करने के लिए आती हैं। उन को युनाइटेड नेशंस, युनिस्को और भारत सरकार की मदद से काम करना होता है। गांवों में जो सबसे नीचे के तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए वह काम करती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए काम करती हैं, इतनी वल्नरेबल सेक्शन की महिलाएं हैं लेकिन आज भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे अत्याचार करने वाला थानेदार हो, बी०डी०ओ० हो चाहे गांव के बड़े लोग हो पुलिस या प्रशासन उनको सुरक्षा नहीं देता। पढ़ी लिखी औरतें जब काम करने जाती हैं चाहे वह सरकारी दफ्तर हो उनको कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ बोल नहीं सकतीं हैं। अन्याय और अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। हरिजन आदिवासियों के बारे में कितनी ही दफा चर्चा हुई है, कितने ही दिन बातचीत हुई है,

इस सदन में लेकिन कोई निदान नहीं है। इसलिये मैं चाहती तो आज भी आपके सामने बहुत से आंकड़े पेश कर सकती थी लेकिन आंकड़ों से कोई बात बनती नहीं है। आंकड़े आपके दफ्तर से मिलते हैं। वस्तु स्थिति बदलेगी नहीं और हालत सुधरेगी नहीं। आज जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का यह डाक्यूमेंट है यह एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा, यह कमीशन एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा जिसको कोई शक्ति नहीं होगी। ऐसे भी इसको कोई शक्ति दी नहीं गई है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस को काम करने का अधिकार देना चाहिये। इंक्वायरी के बाद जो दोषी हो उस को सजा देने का अधिकार भी उन को देना चाहिये था। ऑन दि स्पॉट इंक्वायरी करके ऑन दि स्पॉट उसका डिसीजन होना चाहिय। डिसीजन मेकिंग का पावर उसको देना चाहिये था। जिलों में भी बनेगा, प्रांतों में भी बनाने का फैसला किया है तो इस से केवल एक नया स्ट्रक्चर बना देने से कोई बात बनेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो स्थिति है अगर देश भर में वह चलती रही, देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना इसी तरह से चलती रहेगी तो देश में इनसरजेंसी और टेरीरिज्म और बढ़ेगा। आप चाहे कितनी ही बंदूकें लाएं, कितने ही हथियार लाएं अपने विदेशी मुल्कों को खुश करने के लिए कितने भी कमीशन बनाएं, बात नहीं बनेगी। सबसे पहले हम को अपना घर दुरुस्त करना होगा, आर्थिक स्थिति को दुरूस्त करना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा तभी आपका आयोग कामयाब हो सकता है।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI RAJNI RANJAN SAHU (Bihar): Sir, I rise to support the Protection of Human Rights Bill, 1993.

Sir, we all know that this Bill has been brought forward in *lieu* of the Presidential Proclamation to provide for the constitution of a National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions in States and Human Rights Courts for better protection of human rights and for matters connected therewith or incidental thereto. The object of the. Bill is laudable and it needs the support from all corners. But we have also to see what the reason is for bringing forward this Bill after 44 years of our Independence. Obviously, we all know?

that there have been changes in the entire social scenario, political environment and international order. As the terms "civil rights*, "civil liberties", "fundamental rights" and "fundamental freedom" have got no fixed definitions, so also the expression "human rights" has got no fixed definition. Even the Charter of 1945 does not define human rights in precise terms. The exact meaning of human rights differes from country to country. But its important element remains the same in all countries. Even in the olden days, in the Vedic period and during the Mauryan rule, some rights were equal among the people and everyone had a rights to get himself or herself involved in the governance of the State. So, broadly we can say that human rights concern human development. The basic idea should be the development of man, the development of the human beings as a whole.

Sir, human rights have been accorded a pride of place in our Consitituion also and our Constitution is the greatest document so far as human rights are concerned. We have got an independent judiciary, a free Press, a multi-party democracy, etc. Every citizen has been given the right to live in this world. Every party, at the time of elections, announces some kind of rights in its manifesto which are needed by the people and which are to be given to the people by the party which comes to rule. But, in actual practice, it is being flouted. I do not blame any party. As far as I have understood, the rationale behind setting up this Commission is that some national and international organisations have engaged themselves in illegal violation of rights and there have been such violations by governments also. It should be remembered that every individual and groups of individuals have got the right to live and the right to liberty and right to dignity.

After all, those who are the victims of terrorist acts have got a right to live. And, 1 think, the Commission should also

[Shri Rajni Ranjan Sahu]

look into the violation of human rights by others in an organised manner or otherwise, as also by the secessionist groups or organised groups. The functions of the Commission should also include a provision so that the terrorist and secessionist groups are also brought under its purview. As I have said, mere recommendation of the Authority concerned is not going to help. Otherwise, people will lose faith in this legislation or in this Commission.

Sir, the Human Rights Bill was earlier introduced in May, 1993. But it was thought' that the human Rights Commission Bill would remain incomplete if the human right protection is not given to the individual. So, to remove the flaws which were there in the Human Rights Commission Bill which was introduced earlier and to give effective strength to the recommendations of the Human Rights Commission, this Bill has been brought with a provision in Chapter-2 about the constitution of a National Human Rights Commission: "The Commission shall consist of: (a) a Chairperson who has been a Chief Justice of the Supreme Court; (b) one Member who is, or has been, a Judge of the Supreme Court; (c) One Member who is, or has been, the Chief Justice of a High Court; (d) two Members to be appointed from amongst persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights;" and so on and so forth. But I am surprised why the Chairman of the Backward Classes Commission has been singled out.' Our Welfare Minister who has been very keen in establishing this Backward Classes Commission is here. I want to draw his attention. All Chairman of the Commissions, except the Chairman of the Backward Classes Commission, have been included in this Commission. So, I request the Welfare Minister who is present in the House to take up this matter with the Home Minister.

Sir, the functions of the Commission have been stated in Chapter-3. They are: "To inquire *suo motu* or on a petition by a victim or any person on his behalf into complaint of — (i) violation of human rights or abetment thereof; or (ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;" and so on and so forth. So, the functions have been very broadly defined in this Bill. But I feel that all these functions are recommendatory in nature. They do not give any biting teeth to the Commission.

It can only make a recommendation and the Government may go in for procsecution or may grant relief. And if the recommendation is not accepted, that becomes the end of the matter and the end of the victim and his family.

The other aspect which has been omitted or left out relates to the exclusion of military and other security forces from the purview of this Bill. We can appreciate it but there should be some provision keeping in view the instances of human rights violations indulged in by the security forces and the army in respect of the acts of murder, rape, etc.

The State Governments have also been given the power to constitute State Human Rights Commission to be headed by a former Chief Justice of the High Court and the area has been specified as per List 2 and List 3 of the Seventh Schedule to the Constitution. It is also understood that each District and Sessions Court will be deemed to be the Human Rights Court by the State Government, with the consent of the Cheif Justice of the High Court. It appears very fine on paper. But the effectiveness of this will depend upon the understanding of the person concerned dealing with human rights who may be unaware of the human rights violations and jurisprudence.

Then, the aggrieved person has to file his complaint within a certain time otherwise it will be barred by limitation. This should not be so. If a person is deprived of his right to live or if he loses

the right to live honourably, it would not be fair to say that within a certain time he should file his petition otherwise whatever Injury he has suffered, it will be forgotten and forgiven and he will have no remedy. I think no time limit should be provided for filing a petition, in this Bill. Such a provision could be made in other cases like in other judicial cases, in criminal cases but in case of petition against any human rights violations, no time limit should be prescribed. The aggrieved person should not be made to lose his right to ask for.relief if he is not able to file his petition within certain time limit.

The Commission must have its own investigating machinery to look into the charges of human rights violations. But I think no such provision has been made in this Bill.

We have also to watch the repercussions and also see as to what is going to be the fate of the existing laws like NASA and TADA. We have enough provision under the existing laws and if the proposed legilsation is treated on par with the existing laws, I think the relief that is expected from this Bill, may not come out.

We all know that a large number of cases are pending in the courts already, right from the district court to the Supreme Court. People are unable to get speedy justice. If the cases arising out of the Bill also go to the existing courts, I think the victim would get relief only after he is relieved of the bondage of life, after he attains *Jeevan Mrityu.* Therefore, I suggest that a special provision should be made' to implement the recommendations of the Commission, if at all it is a recommendatory body. A special provision should be made to look into the cases which come under the purview of the Protection of Human Rights Bill.

With these words, I support the Bill with the request that the suggestions I have given may be taken into consideration. Thank you.

SHRI RAMACHANDRAN P1LLAI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome the Protection of Human Rights Bill, 1993. I cannot wholeheartedly support all the provisions of the Bill because the Bill contains certain infirmities and deficiencies. Of course, I am glad to note that some of the major deficiencies and infirmities which were there in the original Bill have been cured. Many of them have been cured. But I do not think the Bill adds any substantial rights than what we already have in India.

The definition of human rights given in the Bill is a very narrow one. Clause 2(d) and 2 (f) refer to it. Clause 2(d) says: "human rights" means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution of embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India'. Clause 2(f) refers to the International Covenants. It says: "International Covenants" means the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on the 16th December, 1966'. It does not mean that all these rights can be enforceable. Clause 2(d) confines human rights to those relating to life, liberty, equality and dignity of the individual and which are enforceable by courts in India. Therefore, only those rights which are enforceable by courts in India come under the category of human rights. That is why I say that this Bill does not add any substantial rights to the citizens of India.

The second aspect is that the concept of human rights is viewed in a very narrow sense in the Bill. It should not be viewed in a very narrow sense.

[Shri Ramachandran Pillai]
Human rights are to be protected in all shperes of life. Civil, political, economic, social and cultural rights are to be protected. Though there is the question as to how much emphasis should be placed on each category of human rights, the importance of economic and social rights should not be ignored. Of course, those rights are the prerequisites for enjoyment of civil and political right. This does not mean that I minimise the importance of civil and political rights. There are certain instances of violating the civil and political rights. The misuse of TADA, the misuse of MISA and NSA, is there. Of course, those misuses are to be cured. I also accept that the civil and political rights are important for the realisation of economic and social rights, but this particular Bill only refers to the political and civil rights; the Bill does not accept the right to food, the right to job, the right to shelter, the right to education, the right to medical facilities. Of course, the right to food is derived from the core of the fundamental right to life. In developing countries millions of people starve from food shortage. It is estimated that 40,000 children die of malnutrition in the world every day. So, what is the attitude of the surplus-producing countries, the developed countries? We all know. They fight with each other to rob the developing countries, the third world countries. They fight with each other to rob the under-nourished children of these developing, third world countries. If there is no food, if children die of starvation, where is the fundamental right, where are the fundamental civil and political rights? What is the meaning of equality when the right to job is not ensured and an unemployed starving man does not have such choice to make between the human right or human dignity and the status of bonded labour?

So, it is a major shortcoming, according to me, that the Bill does not accept these most fundamental and basic rights, the right to food, the right to job, the right to education, the right to

medical facility, the right to shelter, etc. This does not mean that we should not recognise the civil and political rights. Of course, we champion the civil and political rights. What we want is to expose the propaganda that if some political and civil rights are protected, all human rights are protected. Some of the imperialist countries are making this sort of progaganda. We want to expose -that propaganda because these imperialist countries want to confuse the people, they want to conceal the real issues, they want to side-track the issues. This has to be exposed. The most important criticism is that this present Bill serves only to satisfy certain imperialist countries and their pressure; it does not satisfy the real needs of the people in the country. According to me, the other shortcoming of the Bill is that this Bill does not accept the issue of human rights raised by the people of developing, third world countries. The freedom to choose the path of development is being denied by these developed countries, by these imperialist countries, to all the third-world countries. The right to develop is a corollary derived from the most important right to life or right or right to life in a manner that befits 'human dignity. This is being denied by imperialist countries. The developed countries, the multinational companies, not only rob the developing countries, the third world countries, they also impose their path of development on us. That is. always detrimental to the interest

of the third world countries. 3.00 P.M. They also force us to sign

unequal treaties, they also impore conditions to close down our research institutions of science and technology, they ask us to close down our nuclear research, they ask us to close down our missile research and they intimidate countries which help us in many of these fields. This has also happened in the case of the GATT negotiations, the notorious Dunkel Draft. The pity is that the Government is not

showing enough courage to fight back the pressure of these imperialist countries.

The other major shortcoming of the Bill is that the Bill protects the citizens only from the violations committed by a public servant. Clause 12 of the Bill says that. So, those violations committed by a public servant can be taken cognizance of by this Commission. Of course, it ignores the violations committed by the State Governments, it ignores the violations committed by the Central Government, and it also ignores the human rights violations committed by individuals and group. We all know that religion is made use of by a section to intimidate other sections. Caste is also being used. These individuals and groups are making use of these things and they are violating human rights. But this is not brought under the purview of this Bill. That is a serious shortcoming in the present Bill... *(Time-belt)...*

The terrorists are violating human rights. My submission is that such cases should not fall outside the purview of the Human Rights Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): But you are violating the time-limit!

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: That is a most fundamental right. I may be allowed by fundamental right!

The relationship of the national commission with the State Commission also needs more and more clarification. I do not want to read out clauses 19 and 36. If a State Commission takes cognizance of or if a State Government appoints a Commission and if a Commission is inquiring into a particular question, then this National Commission has no authority to go into that question. So, according to me, a contingency may arise. Suppose a State Government wants to cover up a certain thing, it can appoint a Commission, and when that matter is before that particular Commission, the National Commission, as per clause 36, has no authority to go into that particular questio. So all these things require further thinking and further clarification.

I wish to bring to the notice of the Government that the right to select our own path of development is one of our most important rights. This is being denied by the imperialist countries. So, along with the human rights issue, we should take up that issue also. Now these imperialist countries are expressing a certain concern. We know their history, we know their tradition. We know the tradition of American imperialism. They trample on the rights of other countries, they attack other coutries. What they did and what they are doing in the case of Cuba, all those things we all know. Now the developed countries are trying . to impose on us their path of development. So I appeal to the Government that the Govement should come forward to protect our right to select our own path of development. If we fail to do that, ail our talk of human rights becomes only empty words.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Narayanasamy............... Not here. Shri Anant Ram Jaiswal. Before he starts if the House agrees, I would like to request Mr. M.A. Baby to take the Chair.

[Vice Chairmen (Shri M.A. Baby) in the Chair

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, उपसभापति जी, यह सही ही बताया गया कि बहुत ही सीमित उद्देश्य से यह कमीशन गठित करने का बिल लाया गया है। इसमें केवल सरकारी अधिकारियों और अगर खींचतान कर देखा जाय तो सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों के अधिकारों के अतिक्रमण, इस बिल के दायरे में लाए गए हैं, लेकिन जो तमाम तरह के रोज अतिक्रमण होते हैं, उनकी इसमें कोई चर्चा नहीं की गयी है।

मान्यवर, मैं शुरू में ही कह दूं कि जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, हमारे कांस्टी-ट्यूशन में उसके लिए पहले से व्यवस्था की गयी है

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

और उन्हें अंदालत लागू कर सके इसकी भी व्यवस्था है। तो अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को ठीक से लागू करते तो अलग से ऐसे कमीशन की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इतने पुख्ता ढंग से उन तरीकों का वर्णन कांस्टीयूशन में किया गया है और अदालत का प्रोटेक्शन दिया गया है उन्हें एन्फोर्स करने का, इसके बावजूद हम देखते हैं कि इस देश में यह मामला किस हद तक बिगड़ गया है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इसी सदन में चर्चा हो चुकी है कि भागलपुर में पुलिस की हिरासत में लोगों की आंखे निकाली गयीं। मेरे ख्याल से कोई जानवर भी इतना वहसीपन नहीं करता जितना अपने देश में पुलिस करती है। जानवर अगर किसी को मारता है तो उसको एक बार में ही मार लेता है, लेकिन धीरे-धीरे कर के उसकी आंखें निकालना और पूरी जिंदगी के लिए उनको बेकार करने का काम हमारी पुलिस ने किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले 109 और 110 का इस्तेमाल किसी गरीब, बेसहारा आदमी को बाजार से या घर से उठाकर बंद करने के लिए किया जाता था। पुलिस वाले जबर्दस्ती उठाकर थाने ले आते थे और उस आदमी के खिलाफ इतनी ही गवाही होती थी कि फलां जगह यह छिपा था जहां से इसकी कोई जरिए-मार्च नहीं है। उसके पास से खाली एक साबुन, एक मोमबत्ती और एक दियासलाई बगैरा निकली । इतना कह देने पर एक आदमी को सालभर के लिए जेल भेज दिया जाता था। उसका नाजायज फायदा सामन्त लोग उठाते थे, फिर उसकी जमानत करवा के ले जाते थे और उससे बेगार लेते थे। इस तरह यह सामन्त और पुलिस का मिला-जुला खेल था। अब उस 109 और 110 की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आ गया है, टाडा आ गया है जिसमें बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमें के आदमी को जेल में रखा जाता है जबकि कानून के तहत यथा-शीघ्र उसकी ट्रायल हो और जो भी कानून में सजा हो, वह उसे मिले, लेकिन सरकार अपराधों को रोक नहीं पाती और अगर कहीं उग्रवाद आ जाय तब तो फिर कोई सीमा ही नहीं रहती है कि क्या होगा? यह सीमा कहां तक चली जाती है कि महिलाओं के बलात्कार और उनकी मालेस्टेशन भी बचाया नहीं जा सकता। तो जब ऐसी हालत आ जाती है तब फिर लोग उसे सह लेते हैं। आम आदमी जोकि यह सब सहना नहीं चाहता, वह भी कहता है कि ठीक है, लेकिन यह बुरी बात है। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर ये चीजें बर्दाश्त की गयीं और चोर के साथ कायदे-कानून का बर्ताव नहीं

किया गया तो फिर किसी भले आदमी को कानून क
सुरक्षा नहीं मिल सकती क्योंकि यह तो होना ही है
उपसभाध्यक्ष महोदय, देखा गया है कि पहले जैसे 109
110 में लोग पकड़ लिए जाते थे वैसे ही घर औ
बाजार से उठाकर फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया जाता है

हमारा संविधान तो यह कहता है कि किसी आदम
की जान या स्वतंत्रता संविधान में जो विधि दी गई
उसके अनुसरण में ही ली जा सकती है। लेकिन, उसक
घर से पकड़ा गया या बाजार से पकड़ा गया और फि
फर्जी एनकाउण्टर दिखाकर मार दिया जाता है। एक
नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारा ख्याल है, 1980 के
आसपास से, जबसे यह मामला शुरू हुआ, इस हद त
गया कि चार हजार, पांच हजार लोग मारे गए। इस
बेगुनाह लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए औ
प्रतिवेदन दिए गए राष्ट्रपति महोदय को और यहां वह
लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। ज्यों-ज्यों य
लोग मारे जाते थे, त्यों त्यों आप समझ लीजिए कि
डकैती, कत्ल, सामूहिक कत्ल की वारदातें बढ़ती जात
थीं। बड़े पैमाने पर कत्ल और डकैती हुई है। जब बदल
लेने के लिए या अकारण किसी को मारा जाएगा तो फि
कोई महफूज नहीं रह जाता है। अगर मान लीजिए, हमा
किसी आदमी को या हमको मारा जाएगा तो हम
हमदर्दी रखने वाले या हमारे कुटुम्ब के लोग, यह चाहें
कि जिस आदमी ने हमको जबरदस्ती, बगैर किसी कार
से मारा था उससे बदला लिया जाए और नतीजा ऐस
होता है, उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर जो थे उन्हीं
मकान के सामने पुलिस के दरोगा का कत्ल हो जाता है
तो एक जगह हिंसा हो गई तो उसकी कड़ी जुड़ती गई
इसलिए हर सरकार को सावधान रखना चाहिए अप
अधिकारियों को और खासकर पुलिस और सशस्त्र ब
को ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि बगैर कायदे कानू
को बरते हुए बेगुनाह लोगों को पकड़ें और मार दें

इधर हल्ला कुछ ज्यादा हो गया। इस सरकार
उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई यह लाते, लेकि
हल्ला ज्यादा था, दबाव था विदेशी ताकतों का और
यह था कि जो अभी अभी जनरल असेम्बली हुई
युनाइटेड नेशन्स की, कहीं उसमें उनके खिलाफ प्रस्ता

ही न आ जाए, इसलिए इस कानून को जल्दी में लाया गया है। अब जब जल्दी में लाया गया तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं, खासकर के, आप समझ लीजिए, कि किसी तरह की कोई इन्कवायरी आर्मड फोर्सेस के खिलाफ नहीं की जानी चाहिए। उसमें यह खाली गवर्नमेंट से जानकारी मांगेगी और जानकारी पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके फिर गवर्नमेंट को भेजेगी। उसी तरह से और मामलों पर भी इन्कवायरी का जो नतीजा है वह फाइनल वर्ड नहीं है। उसके लिए भी सरकार को रिपोर्ट जाएगी। तो यह जो आयोग बनाया जा रहा है, इसकी हैसियत खाली रिकमंडेटरि है। वह रिकमंडेशन सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, यह सरकार की मर्जी पर है। सरकार ने उस पर कार्यवाही की या नहीं की, बाद में लिखेंगे जरूर, यह व्यवस्था की गई है कमीशन को, लेकिन उसमें कोई आगे की कार्यवाही कर सकता है, इस मामले में यह बिल्कुल साइलेंट है। चाहे कमीशन उस पर एग्री करे या एग्री न करे, लेकिन सरकार से जो जवाब आ गया, उससे उसको संतोष करना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ी खामी है।

मान्यवर, जो सरकार का रिकार्ड रहा है, अगर उसको देखा जाए तो न मालूम कितने कमीशन आफ इन्कवायरी बैठाए जा चुके हैं, बड़े बड़े दंगे हुए हैं सांप्रदायिक उनमें बैठाए जा चुके हैं, लेकिन आगे उनकी रिपोर्ट पर आज तक कोई कार्यवाही की ही नहीं। जो भी सुझाव आते हैं, उनके कारणों पर प्रकाश डाला जाता है, मगर कार्यवाही नहीं। यहां तक सांप्रदायिक दंगों का सवाल है, यह कोई एक दिन में होते नहीं। मान्यवर, जितने दंगे हुए हैं, उसके लिए पहले से कार्यवाही होती है और धीरे धीरे करके मामला इतना उत्तेजित हो जाता है, जिसमें एक कंकड़ी भी आग लगाने के लिए काफी होती है। पहले जो गफलत होती है, कुछ किया नहीं जाता। यह सब बातें जांच-रिपोर्टों में आ गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, जांच की जो रपटें है वह रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं और उन पर कभी कोई कार्यवाही होती नहीं। इसलिए इस कमीशन की रपटों पर भी सरकार क्या कार्यवाही करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या नतीजा निकलेगा। अभी से अगर सरकार चेते और सचमुच कार्यवाही करना शुरू कर दे तो शायद उसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकलें। हां, इससे एक ऐसा माहौल बना[illegible] सकता है। आज जो सरकार है, जिनकी वृत्ति है, [illegible] सरकारी तंत्र है, हमने यह सब लिया है अंग्रेज साम्राज्यशाही से यह तंत्र, उसमें किसी तरह का प्रायः कोई सुधार नहीं हुआ है, सिवा इसके कि हमने अपना कंस्टीट्यूशन बनाया है, बाकी वही पुराने कानून और वही पुरानी सब चीजें हैं।

इसकी वृत्ति थी लोगों के दमन की, लोगों को दबाने की और उनके तमाम अधिकार छीनने की, वह वृत्ति आज भी है। 15 अगस्त, 1947 को भी वह वृत्ति कायम थी और आज वह वृत्ति और ज्यादा बढ़ गई है। नतीजा हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के वक्त में कभी भी लोग घर से पकड़कर मारे नहीं जाते थे, यदि जुर्म किया हो तो उनको अदालत भेजा जाता था और कायदे-कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाती थी, लेकिन आज उसमें बिगाड़ हुआ है। इसलिए हमारे जो संविधान रचयिता थे उनकी यह दूरदर्शिता थी कि जिस तरह का तंत्र हमें विरासत में मिला है अंग्रेजों से, वहां पर इस तरह के विविध लोग हैं, कहीं किसी दूसरे के साथ ज्यादती न हो जाए और उसमें किसी तरह से ज्यादती न की जाए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई और इसे प्रोटेक्शन भी मिला है अदालत से। लेकिन उसके बाद भी हमारी हालत नहीं सुधरी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से, गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक अफसरों के रेप का सवाल है, चाहे वह पुलिस के अधिकारी के जरिए हो, चाहे आर्म्ड फोर्सिस के जरिए हो, उनमें बहुत सख्ती से रोकथाम की कार्यवाई आप करें। यह हुआ है जैसे कि सुभाष चन्द्र बोस ने जब अपनी आजाद हिन्द फौज बनाई थी तो उसमें उसने व्यवस्था की थी कि अगर किसी औरत के साथ कोई फौजी आदमी किसी तरह की भी ज्यादती करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। जब तक इस तरह का कोई डर आप नहीं रखेंगे, यह हरकतें और बढ़ेगी और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन पर रोक रखनी चाहिए।

यह जो कानून आपने बनाया है, इसमें एक व्यवस्था अच्छी है। ज्यादातर जो अतिक्रमण होते हैं वे इसलिए होते हैं कि लोगों को कानून की जानकारी नहीं रहती, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रहती। इसमें व्यवस्था की गई है कि विभिन्न तरीकों से प्रचार और प्रसार किया जाएगा। इसमें यह एक अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका पूरा इस्तेमाल करे, लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे तब शायद जो ज्यादती करने वाले अधिकारी हैं, जो मशीन है ज्यादती करने वाली, वह कुछ दबे और सचेत रहे। धन्यवाद।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मानवाधिकार संरक्षण विधेयक, 1993 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उसने इस अत्यंत मानवीय और महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा करने का मौका दिया।

वैसे तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और जो मानवाधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, उनकी बड़ी व्यापक व्याख्या है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां हमारे पहले भी कुछ आयोग बने हुए हैं, उनका भी बड़ा मानवीय ताल्लुक है चाहे वह अनुसूचित जाति आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो या महिला आयोग हो इन सबके गठन का एक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य रहा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो यह मानवाधिकार आयोग है, जिसका गठन किया जा रहा है, यह एक सशक्त और अधिकार सम्पन्न आयोग सिद्ध होगा, जो लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा, मानव अधिकारों की सुरक्षा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यद्यपि इस विधेयक में जो व्यवस्था है और जो इसका दायरा है उसका केन्द्र-बिन्दु ज्यादातर वह है जो सरकारी तंत्र द्वारा या सशस्त्र बलों द्वारा अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, उस पर इसमें ज्यादा प्रकाश डाला गया है। मेरा निवेदन है कि इंसान के मौलिक अधिकारों को भी इसके प्रकाश में लाया जाना चाहिए। हमारे समाज में मानव अधिकारों का उल्लंघन कई प्रकार से होता है। एक तो जिस तरह से इस विधेयक में यह दिया गया है, इसमें जो व्याख्या की गई है और दूसरे हमारे समाज में भी, समाज के एक वर्ग द्वारा हो, एक विशिष्ट क्षेत्र में हो, धर्म के द्वारा हो, जाति के द्वारा हो, समूह के द्वारा हो, ...और इस तरह से हमारे समाज का जो ताना-बाना है उसकी एक मानसिकता है। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें व्यापक प्रकाश है और इसमें व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा यह आयोग भी कहीं ऐसा आयोग जो मैं समझती हूं कि एक औपचारिक आयोग बनकर न रह जाए।। मैं यह उद्धृत करना चाहती हूं कि पिछले दिनों महिला आयोग का गठन हुआ था। उसमें यह था कि महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए यह आयोग प्रभावी होगा। लेकिन इस आयोग के अधिकारों की जो व्याख्या की गई थी उनको वह अधिकार ही नहीं मिले और इसमें भी हम सब लोगों को कम से कम महिलाओं को भ्रम है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जयन्ती नटराजन ने उड़ीसा में एक मंत्री के द्वारा एक महिला को अपमानित करने का मामला उठाया। यह बड़ा गंभीर मामला था। उन्होंने काफी प्रयास किया। उसका नतीजा क्या निकला? जैसे और भी महिला संगठन करती हैं, यह तो सरकारी आयोग है, अधिकार प्राप्त आयोग है। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ता जायसवाल जी ने उल्लेख किया कि इस आयोग की एक खास बात यह है, वैसे तो इसको सिविल न्यायालय का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो हमारा समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का यह आभास करा देगा, चाहे वह प्रचार माध्यम से हो या मिडिया के माध्यम से हो, अखबार तंत्र के माध्यम से हो या इसकी जो विभिन्न इकाइयां हैं, उसके माध्यम से हो। तो मैं समझती हूं कि समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, मौलिक अधिकारों के प्रति लोग सजग होंगे और अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए स्वयं में एक चेतना जागृत होगी। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि मानव अधिकारों का जब प्रश्न आता है तो हमने इसी सदन में कई सवाल पूछे कि दलितों का, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है और उनके अधिकारों का जो हनन होता है और उनके बारे में जब हम विवरण मांगते हैं तो उन सवालों को कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जबकि यह मामले पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और जो एक सक्षम, सशक्त, साधन है, सुविधा है उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है, मेरी समझ में नहीं आता? तो क्या इन मामलों में कल्याण मंत्रालय से कोई नीति निर्देशन की बात है। यह तो पूरी तरह के कानून और व्यवस्था की बात है। मैं समझती हूं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या है या अन्य अधिकारों की व्याख्या है या अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात है, अपराधियों को दंडित करने की बात है, हमारा संविधान अपने में परिपूर्ण है। अगर उस संविधान के तहत ही पूरी तरह से चला जाए और उसको माना जाए तो मैं समझती हूं कि उस पर चलकर भी अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। यह बहुत अच्छी बात है। महोदय, बिल के अध्याय-2(3) में दिया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा-12 के खण्ड (ख) से खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी जो सिफारिशें हैं या उनके जो सुझाव हैं, उनको लिया जाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात होगी। हमारे नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जो भी कमियां है और जो भी खामियां हैं, वे सब प्रकाश में आ जाएंगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें दिया हुआ है कि सिविल न्यायालय का दर्जा इसको हासिल होगा यानी मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय का दर्जा हासिल होगा। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इसकी व्यापकता को बढ़ाया जाए और इस पर सही मायनों में अमल किया जाए, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए संक्षेप में केवल इतनी ही बात कहना चाहूंगी कि इसका जो दायरा है, उस पर ध्यान दिया जाए और समाज में महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों का जो हनन होता है, उनके अधिकारों की सुरक्षा को इसी दायरे में रखना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यों तो सारे विश्व के मानवों के अधिकार प्रायः समान है, रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय, सम्मान और बराबरी, ये संसार के प्रत्येक नागरिक को चाहिए लेकिन बहुत से देशों में यह देखने में आया है कि मानव अधिकारों का हनन होता रहा है और होता है। कहीं राजनीतिक कारणों से होता है, कहीं आर्थिक कारणों से होता है लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां आर्थिक और राजनीतिक कारणों से तो मानव अधिकारों का हनन होता ही है लेकिन सामाजिक कारणों से भी यहां पर मानव अधिकारों का हनन बहुत ज्यादा होता है। इसका कारण साफ है कि हमारे समाज का जो गठन है, वह असमानता के ऊपर आधारित है। यहां पर जन्म से ही लोग बड़े-छोटे, ऊंचे-नीचे माने जाते हैं। यही नहीं, इस सामाजिक गठन को हमारे ग्रंथों से भी मान्यता मिली है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन हमारे देश में आज भी अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी बहुत मान्यता है। वे धार्मिक ग्रंथ माने जाते है और उन ग्रंथों के अनुयायियों से, उन ग्रंथों पर विश्वास करने वालों से तो लोग झगड़ा मोल ले लेते हैं लेकिन उन ग्रंथों में जो समाज के बहुत बड़े वर्ग—शूद्र और नारी के अपमान की बात है, उसके संशोधन की बात आज तक हमारे देश के किसी व्यक्ति ने नहीं कही। महोदय, शूद्रों का तो इतना बड़ा वर्ग है कि जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और कमजोर वर्ग शामिल है और विशेष रूप से इनके अधिकारों का हनन होता है।

मान्यवर, चूंकि मेरा समय बहुत कम है, इसलिए मैं लंबी-चौड़ी बात न कहकर दो-तीन सुझाव दे रहा हूं और वे संशोधन के रूप में हैं। मेरा नाम बोलने वालों की लिस्ट में नहीं था, अन्यथा मैं संशोधन पहले दे देता। चूंकि मेरी पार्टी के दूसरे सदस्य बोलने वाले थे, उन्होंने समय छोड़ दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं।

पहली बात तो यह है कि इसमे जो मानव अधिकार की परिभाषा की गई है, वह अपर्याप्त है और यह हमारे देश की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। हमारे संविधान में और हमारी संसद ने समय-समय पर जो कानून पास किए हैं उनमें मानव अधिकारों की पूरी परिभाषा व्याप्त है। इसलिए जहां पर यह कहा है कि—

> "Human rights means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or as in Acts passed toy the Parliament."

इसमें ये जोड़ देना चाहिए—

> "from time to time"

जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंस ऐक्ट हमने पास किया, सोशल जस्टिस ऐक्ट हमने पास किया है, और भी बहुत से हैं। तो एक तो इसकी परिभाषा में "from time to time" और जोड़ देना चाहिए।

दूसरी सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि ये जो आयोग का गठन है, इसके पहले चैप्टर के क्लाज 2(डी) में कहा गया है कि—

> "Two Members to be appointed from amongst persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights."

ये व्यर्थ है। इसको साफ लिखना चाहिए। आप जानते है राज्यसभा के लिए सदस्य जो नामित होते हैं उनके लिए साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 80 में कि.......

> "...having special knowledge of or practical experience in respect of literature, science, art and social service."

लेकिन अभी ऐसे लोगों के नामिनेशन हुए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि ये पोलिटिकल नामिनेशन

[श्री संघ प्रिय गौतम]

होते हैं। इसलिए इसमें साफ लिखना चाहिए कि नामिनेशन उन लोगों का होगा जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम कर रहे है जिसका जिक्र इस में किया गया है।

जहां मानवाधिकार आयोग को यह अधिकार दिया गया है—

" Encourage the efforts of non-Governmental organisations and institutions working in the field of human rights."

जो इस किस्म का काम कर रहे हैं इनमें से दो आदमी होनी चाहिए, वरना यह पोलिटिकल नामिनेशन होंगे....(व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन: 6 दिसंबर को क्या हुआ था? मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ था?....

श्रीमती संघप्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदय, हम महिलाओं के अधिकारों के रक्षक है और ये मेरे अधिकार का हनन कर रही हैं....(व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन: आप मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के साथ में बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री संघप्रिय गौतम: तो जो मैंने अर्ज किया, इसमें वह स्पष्ट होना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि इसमें विडंबना यह है कि इस में कई जगह माना गया है कि सिविल कोर्ट का इसका दर्जा होगा। लेकिन यह भी कहा गया है कि "इट विल बी डीम्ड टु बी ए जुडिशल बाडी"। अब इस को अधिकार कुछ नहीं है। धारा 185 और 186 आइ०पी०सी० की कुछ धाराओं के तहत इस को अधिकार दिया गया है कि जहां पर कोई हस्ताक्षर करने से मना करेगा, कोई कागज जमा करने से मना करेगा और कोई कंटेम्प्ट आफ कोर्ट करेगा तो उसको सज़ा यह आयोग नहीं दे सकता। केवल उसके खिलाफ पर मैटर को मजिस्ट्रेट को फारवर्ड कर सकता है। जब इस को इतना भी राइट नहीं है तो यह काहे का जुडिशल बाडी है? यह सेल्फ-कंट्राडिक्टरी है। कुछ इसको अधिकार होने चाहिए। जब वह आएगा, कागज मांगेगा, ऐविडेंस लेगा और कोई कोर्ट की अवमानना करेगा, तो उसके खिलाफ भी यह कार्यवाही नहीं कर सकता तो और क्या कर सकेगा? इसलिए यह सेल्फ-कंट्रेडिक्टरी है। इसलिए कुछ अधिकार इसको देने चाहिए।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेकों आयोग बने लेकिन उन आयोगों का काम निष्क्रिय· है। इसमें एक बात आदरणीय कमला जी ने भी उ थी कि जो अधिकार है, जैसे आरक्षण का संविधान अधिकार है चाहे अनुसूचित जाति का है, जनजाति का या पिछड़ी जाति का है, हमने उसको स्वीकार किया मंडल कमीशन के आधार पर। तो यहां अनुसूचित ज आयोग, जनजाति आयोग और महिला आयोग अ माइनॉरिटी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे तो इस के स होंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष है व क्यों नहीं इस का सदस्य होगा? अगर उन का आरक्ष पूरा नहीं होगा तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? इस यह लैकूना है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी इ का सदस्य होना चाहिए। कम से कम जब तक व आयोग ऐक्जिस्ट करता है। तो इस मामले में मेरा सुझ है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को भी इस शामिल कर लिया जाए।

अखिरी बात मेरी यह है कि जहां पर र मानवाधिकारों का सामाजिक दृष्टि से हनन होता है, कु लोगों ने इस का जिक्र किया कि जहां आज भी गांवों देखा गया है कि जाति जाति के झगड़े हो गए तो किस ने खेत पर जाने से मना कर दिया, किसी ने पशु चरा से मना कर दिया, किसी ने घास खोदने से मना क दिया, गांव समाज की जमीन पर जाने से मना कर दिया तो यह बात भी इस में स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि ज कोई भी कानून हम बनाते हैं या आयोग बैठाते हैं य कमेटी बैठाते हैं हम अपने देश के लिए बैठाते हैं। अपन देश की समस्याओं के लिए बैठाते हैं। हम दूसरे देशों के लिए नहीं बैठाते हैं। यह हमारे देश की समस्याओं के लिए आयोग बैठा रहे हैं। हमारे देश में यह समस्या तो पहले सी ही उत्तर प्रदेश में है कि जाति जाति के अधिकार का हनन कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, वर्ग वर्ग का कर रहा है, अब तो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का हनन कर रहा है और सदन के बाहर तो बाहर, सदन के अंदर उत्तर प्रदेश में भी हुआ है यह आपने देखा। सामाजिक जो हमारा ढांचा है यह इसी की देन है। इसलिए आज हम इस पर विदेशियों का ख्याल न रख कर जो हमारे देश की समस्याएं हैं, सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक ढांचे के कारण जो मानव अधिकारों का हनन होता है यह समाप्त हो। हमारा सारा जोर इस पर होना चाहिए और यही आयोग की मंशा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आदेश का अनुपालन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश): माननीय

उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे मानव अधिकार आयोग पर जो बोलने की अनुमति दी है इसके लिए मैं अनुग्रहीत हूं। मैंने इस सदन में अपने बहुत से साथियों को सुना जिन्होंने मानव अधिकार आयोग के बारे में विचार रखे थे जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने के बाद सितम्बर, 93 में गठित किया गया था और जिसमें उच्चतम न्यायालयं के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे। उसके साथ न्यायमूर्ति फतिमा बीबी, यायमूर्ति श्री टी-कोटउद्यम, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री सुखदेव सिंह कार, हाई कोर्ट के श्री नरेन्द्र दयाल, इसके साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के, महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। बहुत से साथियों ने यहां बताया कि इस आयोग का गठन राष्ट्रपति जी की अधिसूचना से किया गया जो सदन में पारित करने के लिए लाया गया है। वह तो विश्व के मानवाधिकार आयोगों के दबाव से किया गया है जैसे एमनिस्टी इन्टरनेशनल एशियावाद, इन्टरनेशनल कमीशन आफ सिविल राइट्स। परन्तु ऐसी बात नहीं है। मानवाधिकार आयोग का हमारे सदन के नेता और हमारी सरकार के गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण ने अनुमोदन किया और इसे पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। मानव अधिकार आयोग जिसके बारे में रूसी जो एक पाश्चात्य चिंतक थे, ने कहा था — वई आर बोर्न फ्री बट एवरीवेयर वई आर इन चेन। हम जन्म से स्वतंत्र हैं परन्तु हर क्षण, हर कदम पर हम परतंत्र हो जाते हैं समस्याओं से। हीगल ने भी इसकी चर्चा की थी। इसकी चर्चा मैकेवेली ने प्रिंस ने भी की थी। हाब्स और रॉक ने भी इसकी चर्चा की थी। हाक ने लिविएथन में अपने एक ग्रंथ में इसकी चर्चा की थी। इंगलैंड में जो गोल्डन रेवोलूशन यानी स्वर्ण क्रांति आई थी वह भी मानव अधिकार के लिए ही थी। लेकिन मैं सदन में आपके समक्ष यह बयान करना चाहता हूं कि जो हमारे गृह मंत्री ने इसके बारे में आश्वासन दिया है इसको महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद इस सदन में पारित करने के लिए लाया गया है यह हमारा सिद्धांत आज से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक अंग था मानव अधिकार के लिए हमारे तंत्र में, हमारे शासनतंत्र में, हमारी शासन व्यवस्था में पहले से ही है। हमारे सबसे पुराने शासक रंजदेव जी थे। अभी तो हमारे अल्प- संख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी आयोगों के अध्यक्षों को इसमें सदस्य के रूप में रखा गया है। लेकिन पहले स्त्रियों की रक्षा के लिए था और अब हमारे सभी की रक्षा के लिए है। हमारी हर शासन पद्धति में इसका स्थान था।

जिसकी चर्चा हमें प्राचीन इतिहास में रन्तिदेव के संदर्भ में मिलती है जो एक शासक था। सर्व संख्यकों के लिए जो उत्पीड़ित और पीड़ित थे उनके विषय में उन्होंने कहा था—

> ना त्वहम कामये राज्यं......न स्वर्गम् न पुनर्भवाम्।
>
> कामये दुःख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम्।।

मैं राज्य के सुख को नहीं चाहता और न मैं स्वर्ग ही चाहता हूं, न कोई प्रतिष्ठा चाहता हूं। लेकिन जो उत्पीड़ित हैं, पीड़ित हैं और दुखी लोग हैं, वे किसी भी संख्या में हों, किसी भी संख्या में आते हों, उनकी पीड़ा का निवारण चाहता हूं। उसके बाद हमारा जो गुप्त शासन था, उसको भारतीय राजनीति में, यहां के इतिहास में, स्वर्ण युग कहा जाता है, उस समय शकों ने आक्रमण किया। शकों के आक्रमण के बाद यहां रामगुप्त की महारानी जो ध्रुवस्वामिनी थी उसका शकों ने अपहरण किया जिसका वाणा ने हर्ष चरित्र में वर्णन किया है—

> स्त्रीवेशः ..... निह्नुतः चन्द्रगुप्तः शत्रोस्कन्धावार शकपति वधायाऽगमत्।

यानी स्त्री वेश धारण कर शकों के केम्प में, शकों ने वहां पर जो शिविर बनाया था उसमें चन्द्र गुप्त ने ध्रुवस्वामिनी की मुक्ति के लिए स्त्री वेश में प्रवेश करके शकपति का वध करके ध्रुवस्वामिनी को मुक्त किया था। जो ये कह रहे हैं कि विश्व के मानवाधिकार आयोगों के दबाव से भारत में यह मानवाधिकार आयोग बना है, मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था। वहां पर चर्चा में दो-तीन चीजें उठी हैं। लोक संग्रह की बात है। जैसा अभी प्रमोद भाई ने कहा कि यह एक सिफारिशी आयोग है। इसमें अधिकार नहीं हैं। सिफारिशी का मतलब यह नहीं है। उससे जन संग्रह होता है, लोक संग्रह बनता है। गांधी जी कोई प्रधान मंत्री नहीं थे। लेकिन उनकी सिफारिश थी, उनका मत था कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए। हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। इसके बाद जनमत बना और बरतानिया सरकार की जो गुलामी की जंजीरें थी वे टूट टूट कर बिखर गई और हम स्वतंत्र हो गये।

श्री अनन्त राम जायसवालः वह सिफारिशी नहीं था, एक संकल्प था।

श्री शिव प्रताप मिश्र: जी हां, संकल्प था। इसमें भी कहा गया है कि मानवाधिकार सब को मिलें। इसमें यह नहीं है कि कोई प्रचार हो। यह कोई एडवरटाइजमेंट नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है। यह भी एक संकल्प है। सब को मानवाधिकार मिलें, उन्हीं अधिकारों के लिए हमारी परम्परा रही है। हमारे राष्ट्रपिता हरिजनों की बस्ती में रहे, उनके लिए संघर्ष करते रहे, गुलामी के लिए संघर्ष करते रहे। उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करते रहे और उस उत्पीड़न के लिए ही उन्होंने अन्न के नाम पर नमक भी नहीं खाया, अन्न का स्वाद तक नहीं लिया। अपने दामपत्य जीवन के नाम पर अपनी पत्नी तक को भी वे मां कहने लगे। वस्त्र के नाम पर आप लोग उनके चित्र को देखते हैं। वे इतना ही पहनते रहे। इसी से लोक संग्रह बनता है और उस से ही समाज में क्रांति होती है और उस से ही मानवाधिकार जीवित हो सकते हैं, बने रह सकते है।

दूसरी चीज मैं प्रमोद महाजन भाई की बात कर रहा हूं। इस संबंध में कमला सिन्हा जी ने भी कहा था कि वहां पर पुलिस को बहुत अधिकार हैं। उससे मैं सहमत हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पंजाब, काश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में पुलिस और सुरक्षा बलों के अत्याचार हुए थे। जो विधेयक की बात हो रही है उससे हमारा कानून मुक्त है। इससे मैं सहमत हूं। कहीं कहीं पर अपवाद भी होते हैं। हर जगह अपवाद आ जाते हैं। हर व्यक्ति की दो आंखें होती है। लेकिन किसी व्यक्ति की जन्म से तीन आंखें भी हो सकती है। प्रमोद महाजन जी ने कहा कि पुलिस को बहुत अधिकार हैं। पुलिस के अधिकारों को मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूं कि हमारे उप गृह मंत्री जी आज से नहीं दो दिन से एक कागज दिखा रहे है कि एक पुलिस का सिपाही, कांस्टेबल मेरे ऊपर पिटिंग का इल्जाम लगाया है और मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट कर दी है। जो उन्होंने कहा उससे तो सांसद भी मुक्त नहीं है, यह तो मैं जरूर बात मानता हूं। लेकिन जितना आतंकवाद काश्मीर में फैला, जितना आतंकवाद पंजाब में फैला, जितना आतंकवाद पूर्वोत्तर भारत में फैला और जितनी अराजकता तमिलनाडु में फैली, उसके लिये पुलिस जिम्मेदार है, इससे मैं पूरा सहमत नहीं हूं। इसके लिये मैं जो आतंकवादी गिरोह लोग थे उनको भी मैं नहीं कह सकता कि यह उनकी कुचेष्टा से हुआ बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र से और जो लोग हमारे राष्ट्र को क्षत-विक्षत करना चाहते हैं, उनकी प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर उन लोगों ने ऐसा किया। मैं कहना चाहता हूं कि मानव अधिकार के लिये — मैं एक लेख को पढ़ रहा था जिसके लेखक है मुसाफिर हुसैन जी। इस लेख में उन्होंने कहा है कि दाऊदी बोह फिरके में धर्मगुरू सयदना मोहम्मद बुरहुद्दी द्वारा जो व की महिलाओं पर और इस फिरके पर अत्याचार कि जाते हैं, इस पर बुहत बड़ा लेख उन्होंने छापा। उस ध के सिद्धान्त के तहत वहां की स्त्रियां अपने को व सयदना लोण्डी मानती हैं और वहां के जितने पुरुष हैं अपने को उसका गुलाम मानते हैं। वे लोग इससे मुव होना चाहते हैं। दबाव डालकर तो आप उनको मुक्त न कर सकते हैं क्योंकि ऐसा इसका सिस्टम है, ऐसी इसव जम्हूरियत है, ऐसा इसका कानून हैं। लेकिन मैं इत जरूर कहता हूं कि यह मानव अधिकार आयोग सब व साथ लेकर सर्वसंख्यकों को एक बनाये और इस दिश में राष्ट्र को एक डोरी में बांधे जिससे इसका विघटन हो और राष्ट्र एक रह सके। क्योंकि जब राष्ट्र ही सुरक्षि नहीं रहेगा, जब राष्ट्र ही एक नहीं रहेगा तो न मान अधिकार होगा, न यहां पर अल्पसंख्यक होंगे और बहुसंख्यक हांगे, यहां पर कोई भी संख्यक नहीं र जायेंगे तो यह देश विघटित हो जायेगा। इसके लि हमारी जो सुरक्षा सेनायें हैं, जो नौसेना है जो सुरक्षा ब हैं, उसमें उनके कार्यों में विक्षेप न हो, यह भी रहे, इसव लिये इस मानव अधिकार विधेयक को इस सदन में पा किया जाय। इसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Protection of Human Rights Bill, 1993. And I would like to make certain observations. Sir, we have got personal laws, special laws; I mean, for every situation, we have got a compendium of laws. Now, after 27 years, we, being a party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, have thought it fit to enunciate a Bill and thus an Act to preserve human rights in our country. Sir, what I feel, is nowadays, the guardians of law, the persons whom we expect to be the guardians of law, themselves are the violators of law. There have been a number of instances where deaths have taken place in lock-ups. Also, a number of rape cases in police stations and lock-ups have also come to

our notice. In many international fora, it has been felt that India was a country where law was being violated and law was being swallowed by the guardians of law themselves. Sir, a case was reported in the year 1992—we have also mentioned about it before. A Scheduled Caste woman was taken into custody in Annamalai Nagar at Madras. In this case, a Scheduled Caste woman was raped by all the people in the Station, right from the Sub-Inspector to the Station Writer, right in the presence of her husband. Not only this, when her husband went to her rescue, he was beaten to death and this case was converted into a suicide case. Much was said about this. It was brought to the notice of the Central Government also. After much pressure, a case was filed. Now she is fighting for her rights in the High Court as well as in the district courts. The main reason why I support this Bill is it is high time that such a Commission was constituted, because the Minister thought it fit to have such a Commission and also because he wanted that human rights should be preserved and, finally, because this is a genuine case. This Bill must be put into practice in its letter and spirit. I can put it that way.

Now, I want to refer to the constitution of the Commission. In the Objects and Reasons of the Bill, it is stated:

> "The Chairpersons of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Women and minorities or the nominees, will be the ex-officio members."

I don't know why the Chairman of the National Commission for Backward Classes is not included. They have not explained why they have omitted him. I don't know whether it is inadvertence or is done intentionally. But I bring it to the notice of the minister and request him to include persons belonging to the most backward classes as ex-officio members.

In the same Objects and Reasons of the Bill, in sub-para (3) of para 4, it is stated :

> "(3) The Commission will be a fact finding body with powers to conduct enquiry into , complaints of violation of human rights..."

It should not be just like any other Commission. We have got various types of Commissions, commission to go into some riots, commission to go into an air crash, etc. These commissions do have powers of a civil court. They enquire into the matter, examine witnesses, per use documents and finally submit a report to Parliament. But what happens after that? What happens is that most of these reports, 99.7% of the reports, simply gather dust. No follow up action will be taken. So, this Commission—I wish to submit—should not be one such commission. It is high time and wc thought it fit to have a commission, Therefore, this Commission should be a Commission of action and should not be like any other Commission which will write a report and submit it to Parliament and allow the report to gather dust in the Parliament Library. The main thrust of the Commission should be action. This is what I submit. It is not enough to have a Commission which would report facts to Parliament.

Coming to other provisions, there will be two types of Commissions. Clause 21 contemplates constitution of State-level Commissions. The word used is 'may'. I want to know from the Minister what the position will be if a State does not have a Commission. The word used arc, "The States may constitute a Commission". What will happen if they don't want to have this headache? They will not constitute it because they will try to avoid this headache. In such a case, what will happen? I want to know if those States have to apply to the Central Commission. This is what I humbly submit to the hon. Minister.

[Shri Tindivanam G. Venkatraman]

Clause 20 says that the Commission shall submit an annual report to the Centkal Government and to the State Government concerned which should be laid before each House of Parliament and with regard to the State Commission, the report should be laid before the State Legislature concerned. Both these reports should be laid on -the Table of each House of Parliament or State Legislature along with a memorandum of action taken or proposed to be taken. They. should not lie without action. Then, with regard to the initiation of proceedings, the Commission may, either on its own motion or on receipt of a petition, seek a report from the Central Government. This is in clause 19(1) (a). Clause 19 (1) (b) says that after the receipt of the report, it may either not proceed with the complaint or, as the case may be, make its recommendations to that Government. Here I feel that most of the cases will go out of this provision. Suppose it seeks a report from the Central Government. We know the type of red-tapism that is there. A case reported in 1990 will come up for action only after ten years. So, there is no point in saying that the Commissioin will seek a report from the Central or State Government. This will not serve the purpose for which this Bill has been brought forward. Therefore, I feel that this clause needs an amendment. When there is a petition, action should be taken *suo mow.*

With regard to the procedures, this Commission has been given powers to regulate its own procedures. That is the case with all Commissions. So, there cannot be two opinions on this.

Clause 11 says that the Central Government shall make available to the Commission an officer of the rank of the Secretary to the Government of India who shall be the Secretary-General of the Commission. That is O.K. With regard to sub-clause (b), I would like to say that 1 beg to differ here and I would like to submit that there should be a separate department because, as I have said earlier, police officers simply swallow the law and there is no point in saying that such police and investigative staff should be provided. Even if the officer is not below the rank of DG of Police, it is no use because he also one of them. There should be an independent department which must do the investigation and when it comes to the question of report, let a charge-sheet be issued under section 173 of the Cr. PC. Let the officers of the Commission do the investigation independently without the assistance of police. This should be done if you wan to have a clear case and the investigation to be free from interference. We all know what happens in cases of deaths in police lockups where policemen or public officials are involved. Out of a hundred cases, in how many cases the inquiring officer fixes the responsibility on the guilty official? The inquiry officer is generally the District Magistrate or Sub-Collector or Collector who will only write in favour of the police or other officials. In suicide cases, the post-mortem certificates have been given like this. So, the same will be the fate of the inquiry conducted by this Commission if it employs officers of the police department. It must have an independent body to inquire into cases. And it can be charge-sheeted and also laid

4.00 P.M.

before the court under Section 173 of the Criminal Procedure Code, just like prosecution is launched by the police authorities.

Sir apart from that, I would like to submit that there is one sub-clause (c), under Clause 12, which says that the Commission shall visit, with the prior approval of the State Government, any jail to study the living conditions of the inmates and make recommendations thereon. Sir, the Commission is being headed by a Supreme Court Judge.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY) : Please conclude. You have taken much -time.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : I will take just another two minutes. Section by Section. I am going. Just I am winding up.

Sir, the Commission is headed by a Supreme Court Judge. Then there is no point in saying this. The Supreme Court Judge has got the power. Just formally he can intimate, and he need not seek permission. But that also will be a dilatory tactics of putting forks in its functioning. Prior intimation and getting permission and all that is nothing but putting forks in giving justice. *(Interruptions)* About intimation, my friend says that it has been amended. In that event, I have nothing to say. I stand corrected.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) in the Chair.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: So, that is what I would like to submit. Regarding...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Vcnkat-raman, you have to conclude now.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Just one minute. Sir.

SHRI S.B. CHAVAN: Leave rest of the Sections for others.

SHRI TINDIVANAM G VENKATRAMAN : There are other speakers also. They will Cover that point.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: I know that, Sir. But I must make my submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Venkutraman, your party's time was four minutes. You have taken more than 15 minutes.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Just I will sec whether I have left out any point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You can raise thai point in the Third reading, it you waul.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Therefore, Sir, if this is to be more effective, what I have suggested is that this Conirnission should not be a dumb-founded Commission, just like other Commission, writing a report, submitting a report and washing off its hands. The Commission must be a really effective one, it must be an active one, and also must be a Commission for the purpose for which it is being chalked out and is being brought through this Bill.

With these words, Sir, I thank you for having given me this opportunity.

SHRIMATI URMILLABEN CHIMANBHAI PATEL (Gujarat): Mr. Vice Chairman, Sir, I support the Bill and I congratulate the Government for brining before the House this Protection of Human Rights Bill.

Sir, in this civilized world, discrimination prevails in all parts of the world in the name of class, caste, religion, sex, community, race, colour and in many other ways. We know that the Blacks have always been dominated by the White people, and they have been a prey to the atrocities of many types all over the world. At times, the Brown people are also taken as Black people and are humiliated. This type of atrocities is very common. And even the developed countries also coerce the developing countries, the Third World countries. And in the name of globalisation, the developed countries want to control the developing countries in this way. The society is facing so many types of atrocities.

.Sir, coming to our Indian society, we find that the social structure of our society is based on caste system.

The main feature of the caste system is caste hierarchy. Brahmins are at the top and Shudras arc at the bottom. In between the Shudras and the Brahmins, we have about six thousand castes and sub-castes. The Shudra communiy is supposed to serve the upper caste people. They give service to the people. Yet they

[Shrimati Urmillaben Chimanqhai Patel]

are ill-treated in many ways. Moreover there are untouchables and they are outcasts. They are not part and parcel of the so called Hindu social structure. They are not accepted as human beings by the caste society. They are the lowest among the low, and as you all know, they are considered to be polluting even by simply touching upper caste man. In this way, so many atrocities are being committed on them. They have no civil rights, no political rights and no economic rights in practice. They have no status in the society and many disabilities are inflicted on them. If there is a minor breach, they are penalised heavily. They have to face atrocities from the upper caste people. Sometimes their huts are burnt; sometimes they are boycotted by the society; sometimes they are severely beaten; sometimes they are burnt alive. They are humiliated every moment. They cannot enter a temple. They cannot wear clean clothes. They cannot even wear shoes and they cannot freely move in the market and if they do so, they are humiliated or at times beaten up. They are also subjected to work as bonded labour. Your might have heard of cases where the untouchable women are sexually exploited; they are raped, and this is considered to be a normal thing in their case; They cannot lodge a complaint with the police or with anybody else. The strange thing is that when the upper caste people rape the untouchable women, there is no danger of any pollution but when they go out or enter into any upper caste family for any reason, they are taken to have caused pollution...............

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Try to be brief because your party's time is exhausted.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: No, I would like to take some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): But we are running out of time.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: But I gave my name two days back.

Same is the condition of the tribal people living in the interior of jungles, in the hills and other places. Though they are not considered untouchables, they are not given the status of civilised people. They have to bear with the exploitation and atrocities.

Now I would like to point out the position of women in our Indian society. Women have always been given a secondary position in society and are supposed to live within the four walls of the house. They are kept illiterate, totally dependent on men. They are supposed to serve the family. They face the same conditions as are faced by the backward classes in our society. They have to face atrocities from the family members as well as from the society. They are even sexually exploited. In some cases they are forced to leave the house. They are misguided and taken away to act as prostitute and at times they are forced into adopting the profession of a call-girl. We know of the system of Devadasis in the southern parts of our country. Even in the northern parts of India we have known of cases of burning of women. We know of cases where women are* forced to burn themselves at the time of the husband's death and that is called Sati Pratha, a very glorious name given to the system.

But it is after all burning of women, forcible burning of women.

Even the children in our society are not taken proper care of. Particularly, in the case of the girl child, there is always discrimination. In the uperbinging of the boy and the girl, there is discrimination. When they have the right to education, at the time when they are to be in school, they have to work hard. Further, no proper treatment is given to them at the work-place. This is our social structure.

We all know that we have not adopted democracy at the political level. But we have not adopted democracy at the social

level. So many kinds of inequalities are prevailing in the society. That is why we see exploitation and all sorts of atrocities committed on these people. The upper castes have a vested interest in preserving the lower castes. They want to have a domination over them. That is why the atrocties are increasing day by day.

After independence, by law, by Constitution, the lower castes have equal rights, equal opportunities. They are fighting for their rights, for their status and for their position. The upper castes feel that they are losing their superiority over them. They want to maintain their domination and that is why we see the chain of atrocities on the lower castes. *(Tune-bell ring)*

I would like to bring to your notice ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, you have spoken for more than ten minutes.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: I would like to bring to the notice of the hon. Minister certain points which should be taken care of. In regard to the composition of the Commission, the Chairperson of the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been included. However, if the Chairperson is from the Scheduled Caste, a Scheduled Tribe person cannot come and vice versa. The Problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are quite different and the atrocities committed on them are also quite different. Therefore, if the Chairperson belongs to the Scheduled Caste, a Scheduled Tribe person can be co-opted. I would also like to point out that the other Backward Classes have been given no representation in the Commission. I suggest that some provision may be made in this regard.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you, Madam.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: I would like to mention one more point.

THE VICE-CAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, the Congress Party's time is 53 minutes. This has been exhausted. They have taken more than one hour.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: In the end, I would like to say that this Commission should not be a Commission only in name as in the case of the National Commission for Women. It has no powers, no facilities and no budget. In the same way, if this Commission is not given proper facilities, enough powers, enough finance and the structure to work, it would only be a Commission in name. Therefore, I hope proper facilities would be given to the Commission if it has to work in an effective way. A well-known poet of Gujarat, Shri Sundram has said: मानवी मानव थाय तोये बस। If a man becomes a man, it is enough. If the Commission could ensure the dignity of the individual, it would be doing a great service to the society. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Madhavan. Your party's time is three minutes. You have to adhere to it.

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome this Bill. The Government is coming forward to appoint Central and State Human Rights Commissions. This would go a long way in meeting the criticisms of international bodies about our executive. Police and executive excesses would be checked. There would be an independent forum to enable the victims to voice their grievances.

International organisations have voiced not only against the Indian Government but also against the Militants they have charged even the U.S. Administration for violation of human rights. Armed opposition groups committed numerous human rights abuses, including hostage-taking, torture, and deliberate and arbitrary killings. Reports, of such abuses were mainly received from Jammu and

[Shri S. Madhavan]

Kashmir, Punjab, Andhra, Assam and North-East States. The reports rap the Government for holding thousands of political prisoners under TADA and NSA, for torture of suspects in custody and the rape of women in police cells and army custody, and accuse senior officials of participating in routine cover-ups by police of deaths by torture. Only 6 out of 415 cases of custodial deaths which occurred between 1985 and 1992, where police officers were tried and convicted for deaths of detainees in their custody. Only in 14 out of 415 cases compensation was paid. In India hundreds of political activists were extra-judicially executed and scores more disappeared in conflict zones. This is the common experience. I had my own experience. My party MLA was detained under a detention law. I had to spend from my party funds more than Rs. 1 lakh to get him released. Wc had to get justice only from the Supreme Court. So, there are points if they make such allegations. Supreme Court had to come to the rescue of victims in a number of cases. In one case the Supreme Court awarded exemplary damages of Rs. 1.5 lakhs to the mother whose son was killed in police custody. His body was thrown on a railway line to show that he had died in an accident. In another case the Supreme Court awarded Rs. 3 lakhs compensation to the widow and children of the victim who died in police custody and directed the administration to sanction prosecution of five police officers and a sub-divisional magistrate. So, there are cases in which excesses have been committed. There are mass rapes by soldiers and police personnel. This has happened in our country.

I understand there arc instructions and rules which prohibit late-night searches and the right of soldier to enter houses in which only women are there. I request the Government to implement these instructions and rules in letter and spirit.

Coming to the Bill, I have to make some suggestions. One of the clauses says that only Chief Justices can be appointed as the Chairpersons. The Government is restricting the scope because at times the Cheif Justices may not be available and at times some of them may not be willing to hold this office. So, I have given an amendment to include the seniormost Judges to be the Chairpersons.

Then there must be an appeal provision against the findings of the State Commission. The Central Commission has got powers under Lists I, II and III and the State Commission has powers under the State List and the Concurrent List, but once the State Commission has started an inquiry, the Central Commission cannot enquire into it. We all know that complaints are generally received against the State police, the political bosses instigating police and the higher ups in the executive protecting the high-handed police officers. So, there may be cases where they may not be able o get justice at the level of the State Commission. There must be a provision for appeal against the findings of the State Commission before the Central Commission.

Coming to Clause 12(c) and 12(d), there is a provison empowering- the Commission to send prior intimation to the Government. There are cases in which excesses by jail authorities are committed. These cases will come to the Commission. What can they do at that time? A number of High Court judgements and Supreme Court judgements have pointed out the ill-treatment of prisoners by jail authorities. So, I have given a suggestion that there should be a proviso that if there are complaints to the Commission about the ill-treatment of the detainees in jail, then the State or the Central Commission must have powers to make surprise visits and find out the truth. Otherwise, the purpose of the provision will be defeated.

About appointment of Special Prosecutors for Human Rights Courts at district level, I welcome the provision, but the appointment must be from the

advocates recommended from the panel of the Chief Justices. The High Courts must be consulted before appointing the Special Public Prosecutor." Even the Cr. P.C. has that rule for Sessions Court. Otherwise, political appointments will take away the rights of the people.

About violation of human rights, after the expiry of one year they cannot inquire into them. But there are cases—I have pointed out—and because of vested interests these are committed. So, if the limitation of one year is there it will be very difficult. Therefore I have given an amendment that at least in cases where the vicitims are able to adduce reasons before the Commission for the delay there must be exceptions and the Commissions must be empowered to inquire into these cases also. Otherwise trust will not come out. So, that provision must be there under clause 36.

Thank you.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन में ह्यूमेन राइट्स बिल के ऊपर चर्चा हो रही है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): यह कांग्रेस पार्टी का समय तो पहले ही खत्म हो चुका है।

चौधरी हरि सिंह: नहीं, खत्म नहीं हुआ है, तभी तो मुझको समय मिला है।

श्रीमती मीरा दास (उड़ीसा): ....**(व्यवधान)** जब ह्यूमेन राइटस के ऊपर चर्चा हो रही है तो महिलाओं को बोलने से क्यों बंद कर दिया गया। .....**(व्यवधान)**

चौधरी हरि सिंह: मैं संक्षेप में अपनी बात कहे देता हूं, आप नाराज न हों, मुझ पर थोड़ा रहम खाइए आप। उपसभाध्यक्ष जी, यह जो ह्यूमेन राइट्स बिल है, यह बहुत अच्छे समय पर पास किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के अखबारी दुनियां के जो लोग हैं उसमें बड़ी चर्चा रहती थी हिन्दुस्तान में ह्यूमेन राइट्स का आदर नहीं हो रहा है और यह एक साजिश के मातहत होता था। आप जानते हैं कि हमारा जो पड़ौसी देश है वह किस तरह की रहकतें करता था, उनको भूल जाता था, उनकी हरकतों को छिपाने के लिए, मर्डर्स के छिपाने के लिए, किडनैपिंग के लिए, अफसर, कर्मचारी, मजदूर इन सबका मर्डर जो पंजाब में, कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में और जो पूर्वी हिस्से में हो रहा है उस सब पर पर्दा डालने के लिए और हमारे देश के कुछ हिस्से में बगावत पैदा करने की जो साजिश थी, यह उसका हल्ला मचा रहा था, शोर मचा रहा था। तो यह उनकी जुबान को बंद करने के लिए यह बिल बहुत अच्छे मौके से लाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिन्दुस्तान के बारे में यह राय साफ है कि हिन्दुस्तान में जो संविधान है, जो हमारा विधि नियम है, जो हमारा कानून है, वह सारे ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के लिए बहुत सफिसिएंट है। लेकिन जो फिर भी वह राजनीतिक प्रभाव के लिए यह जो पैदा किया जा रहा था, उस वातावरण को सारी दुनिया में घूम-घूमकर के और जो हमारा पड़ौसी देश इस बात को कर रहा था, जबकि उसके हिस्से में आप सिन्ध में जाकर देखें कि मुजाहिर के साथ वहां क्या हो रहा है? वहां सिन्धी लोगों के साथ क्या हो रहा है? इसाईयों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है? वोटिंग का राइट उनको प्रोपर नहीं है। वहां सिंधियों पर क्या-क्या अत्याचार हो रहे हैं, थाने में उनको मार दिया जाता है। बुरी से बुरी चीज जो ह्यूमेन राइट्स के हनन की हो सकती है, वह हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में हो रही है। जबकि वही सबसे ज्यादा ह्यूमेन राइट्स के बारे में हिन्दुस्तान पर ऊंगली उठा करके यह इशारा करता रहता था। माननीय होम मिनिस्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बिल को वे आज कानून की शक्ल दे देंगे, यह अच्छा हो जाएगा, सदन पास कर देगा। तो मैं कहना चाहता था कि जो सारी दुनिया के अंदर हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रपोगंडा था, वह आज से खत्म हो जाएगा। मुझको बड़ी खुशी है कि यह जो कमीशन बना, इसका जो चेयरमेन है वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जानेमाने और ह्यूमेन राइट्स के जो लोग प्रेक्टिस करने वाले हैं, जो अखबारों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, उन्होंने ह्यूमेन राइट्स से ताल्लुक रखने वाले बहुत अच्छे-अच्छे जजमेंट दिए हैं। यह जो इनकी नियुक्ति हुई है, बहुत अच्छी हुई है। ऐसे एक्सपीरियंसड लोग कहां मिलते हैं, यह सौभाग्य है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून के जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इस बात को महसूस करते और कहते भी हैं। मेग्जीन में आता है कि हिंदुस्तान में ह्यूमेन राइट्स कमीशन का जो चेयरमेन है वह ह्यूमेन राइट्स को प्रोटेक्स करने के लिए एक अच्छा इंसान है।

मान्यवर, इसके अंदर अभी मेरे साथियों ने कहा -(घंटी)- मेरी तो बात ही शुरू नहीं हुई है श्रीमन्।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You have to conclude now.

चौधरी हरि सिंह: मैं खत्म करना चाहता हूं। आपका बड़ा प्रेशर है, उधर से भी नाराजगी है। मैं साथियों की नाराजगी नहीं लेना चाहता।

मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी मामलात हैं प्रदेश सरकार के सामने और केन्द्रीय सरकार के सामने, चाहे वह हरिजनों पर अत्याचार के मामले हों, चाहे गांवों को जलाने के मामले हो, कहीं भी सरकार ने कोताही नहीं की है और जो वुमैन कमीशन बनाया गया है उस के चेयरमैन इस कमीशन के सदस्य होंगे। यह बहुत अच्छी मांग है, कि बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी एक मेम्बर इसमें होना चाहिये। यह बहुत जरूरी है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा कर देंगे और हम इसके लिए उनके बहुत आभारी होंगे। जिसने भी यह सजेशन दिया है, यह बहुत अच्छा सजेशन है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कमीशन अपने आप में संपूर्ण नहीं है। यों अगर दोष ढूंढने लगेंगे तो पीनल कोड, ताज़ीराते हिंद, कोई भी कानून पूरा नहीं है लेकिन आज की परिस्थितियों में साधारण आदमी भी जो पुलिस कप्तान से डरता है, बड़ी एथोरिटिज़ से डरता है, पूंजीपति, जमींदार से डरता है, वह आसानी से सिर्फ एप्लीकेशन दे करके कार्यवाही करवा सकता है निर्भीक होकर। यह जो अपार्चुनिटी उसको मिली है अपने हकूक की सुरक्षा के लिए इस अनोखे कमीशन के रूप में यह मौजूदा सरकार की अनुपम देन है उन लोगों को जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जिनके हकों का हनन किया जाता है।

महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि यह कमीशन अपने आप कार्यवाही कर सकता है, अखबारों में पढ़कर, व्यक्ति जानकारी हासिल करके। यह तो सुपर कांस्टीट्यूशन हो गया। इसके रहते हुए अगर किसी नागरिक के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती, तो मैं समझता हूं कि यह दोष सरकार का नहीं होगा बल्कि जो अत्याचार सहने के आदी हो गए हैं, उनका दोष होगा। अत्याचार से लड़ने की क्षमता जिसमें भी है, यह उसके लिए बहुत सार्थक है। इन चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है, उसमें कुछ खामियां तो हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उन खामियों को देखते हुए भी यह एक अच्छी शुरूआत है और इसीलिए आगे चलकर जैसा-जैसा हमको अनुभव होगा, वैसा-वैसा उसको संशोधित करना चाहिए। हमारा यह ख्याल है कि अभी जो दुनिया है उसमें मानव अधिकारों के लिए एक बहुत ही जाग्रत भावना काम कर रही है। ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता किसी ऊंचे धरातल पर पहुंचने के लिए विश्व भर में इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक दूसरी टेंडेंसी भी है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, फंडामेंटलिज़्म के नाम पर झगड़े होते हैं और यह कन्फिलिक्टंग बात होती है। लेकिन जो मानव अधिकार आंदोलन है, यह विश्वव्यापी ढंग से चल रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि यहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या दूसरी चीजों के नाम पर झगड़े होते हैं।

महोदय, हमारे भाजपा के मित्र महाजन जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कहीं, जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि इस देश में हर साल 500-600 हरिजन हत्याएं होती हैं। इसलिए अगर एक अलग कमीशन उसके लिए रहेगा तभी उसकी जांच हो सकेगी। इसलिए उसको रखना चाहिए। यह किसी के तुष्टिकरण करने की बात नहीं है बल्कि जीवन की यथार्थता है। उसी तरह मुसलमानों की बात है, माइनोरिटीज की बात है। मेरा ख्याल है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ मुसलमान ही माइनोरिटीज नहीं है। अगर कश्मीर में हिंदू हैं तो वे माइनोरिटी हैं, नागालैंड में हिंदू है तो वह भी माइनोरिटी है। इसलिए इसको उस ढंग से देखना चाहिए और इसको जिस रूप में हमारे भा०ज०पा० के मित्र लोग ले रहे हैं, वह गलत है। मैं समझता हूं कि इसमें अल्पसंख्यक और महिला कमीशन का मेंबर होना भी चाहिए। साथ ही ओ०बी०सी० के मेंबर को लाने की बात है, खासकर अत्यधिक पिछड़ों को, वह भी इसमें होना चाहिए। अभी हम इस विधेयक में कोई संशोधन पेश कर सकें, वैसा मौका तो नहीं है।

मैं समझता हूं कि अभी आप इस बिल को पास कर लीजिए, संशोधन तो बाद में आते रहेंगे। लेकिन इसको मात्र तथ्य खोजक कमेटी न रहने दें। हम गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि एक ऐसा कन्वैंशन बना दें कि यह कमीशन जो भी रिपोर्ट दे, उसको सरकार माने और उस पर कार्यवाही करे। यह बिना कानून के भी हो सकता है। दरअसल कमीशन और कोर्ट में फर्क है। इसलिए अगर सारी बात यह कमीशन ही देखेगा तो आपकी कोर्ट क्या करेगी?

हम आपको यही कहेंगे कि यह कंवेंशन बन जाए हमारे देश में कि कमीशन जो सिफारिश करे उसको आप लागू करें।

एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर जांच के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले यह उचित नहीं है साधारणतया स्टेट गवर्नमेंट से आप पूछ लीजिए लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि जेल वगैरह में सरप्राइज विजिट करने चाहे तो यह अधिकार उन को दे दीजिए। जेल में आप भी जरूर रहे होंगे, हम तो भुक्तभोगी हैं, कैसा जीवन वहां बिताते हैं यह आप जानते हैं। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी होंगे यहां और कुछ नए किस्म के लोग भी आ रहे हैं संसद में और ऐसेम्बलियों में राइफल और बंदूक वाले, वह भी कई बार जेल गए हुए हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता नहीं है उसकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे लेकिन आपसे अनुरोध है कि कमीशन को अधिकार दीजिए कि सरप्राइज विजिट कर सकें।

यह जो आपने प्राविजन किया है कि जिला जिला में जो आलरेडी कोर्ट है उस को ही अधिकार दे दिया कि मानव अधिकार के उल्लंघन को देखे। यह सबसे बड़ी डेंजरेस बात है क्योंकि कोर्ट्स आलरेडी ओवर-बर्डन्ड है। उनको इतना ज्यादा काम है कि वह अपना ही काम नहीं सम्भाल पाते हैं जिस कारण न्याय पद्धति असफल हो रही है।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण: उसके लिए अलग सेशन कोर्ट का भी प्राविजन है....

श्री चतुरानन मिश्र: हम कहते हैं कि आप "भी" बोल देते हैं तो हमें बड़ा अखरता है। इसलिए आप कहिए कि यह सेपरेट होगा तो आप सचमुच में बहुत बड़ा काम कर सकेंगे।

इसी तरह से इंटेरिम रिलीफ की बात आप ने कही है कि उसके लिए कमिशन सिफारिश करे। अगर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज यदि इंटेरिम रिलीफ तय कर देता है तो फिर आपके अंडर सेक्रेटरी और सेक्शन आफिसर के पास वह जाएगा। यह हास्यास्पद है। हम अगर रहते तो हम कमिशन से रिजाइन कर देते। कमिशन को आप तुरन्त राहत देने का अधिकार दीजिये।

इसमें जो एक साल तक के केस लेने के लिए कहा गया है वह साधारणतया हो सकता है, लेकिन मान लीजिए हम अभी प्रिजनर हैं और 5-10 साल से जेल में पड़े हुए हैं, हमारा ट्रायल नहीं होता है। अगर आप कहेंगे कि एक ही साल का रहेगा तो हम तो धरती छोड़कर चले जाएंगे, तब भी मानव अधिकार नहीं मिलेगा। इस को कुछ बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे अन-लिमिटेड हम नहीं चाहते हैं, नहीं तो वह काम ही नहीं कर सकता है, लेकिन इस को सही ढंग से रखिए।

एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अमरीका या दूसरे देशों में पार्लियामेंट के अंदर, सीनेट में मानवाधिकार की एक अलग कमेटी होती है। आप ऐसा कीजिए कि हमारी संसद में भी मानवाधिकार की अलग कमेटी रहे जो हम भी बोल सकें कि लास ऐंजेलस में क्या हो रहा है। हमारे यहां बैठे विदेश मंत्री भाटिया साहब तो बराबर विदेश जाते हैं, तो इन को काश्मीर की रिपोर्ट वह दे देते हैं। तो हम भी उन को दिखा सकें कि लास ऐंजेलस में क्या हुआ, तो यह सही उनका जवाब होगा।

अब हम आप से कहना चाहेंगे कि कमीशन तो आप बना रहे हैं तो आप अपने को तैयार कर लीजिए। हमारा ख्याल है कि आप ने इस के लिए देश को तैयार नहीं किया है। अगर आप यह कमीशन बनाने का कानून पास कर रहे हैं तो देश को तैयार करना अनिवार्य है। संयोग से यहां पर हमारे मानव संसाधन मंत्री जी बैठे हैं, उन को सुनाकर मैं कह रहा हूं कि क्या यह संभव है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का फंक्शन और कांस्टीट्यूशन में जो प्रावधान है वह हर एक बच्चे से लेकर कालेज तक क्लास के सिलेबस में एक सब्जेक्ट बनाकर दे सकें ताकि वह इससे अवगत हो सकें नहीं तो दारोगा जी आते हैं वहीं से महाविद्यालयों में जात-पात ले के आते हैं। इसलिए सिलेबस को चेंज कर दीजिए इसके साथ ही पुलिस की जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में और इंवेस्टिगेशन जो पुलिस के लोग करते हैं और वह कहते हैं कि मारेंगे नहीं तो अपराधी कबूल नहीं करेंगे, बदमाश बोलेंगे नहीं, तो मैथेड आफ इंवेस्टिगेशन चेंज करें। अगर आप रियली चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा हो सके तो जैसे विदेशों में इंवेस्टिगेशन का जो मैथड है उसको अपनाकर आप पुलिस इंवैस्टिगेशन के मैथड को सुधारें।

मैंने पहले ही आप से कहा कम से कम समय में आप न्याय दिलवा सकें, इसकी व्यवस्था करें नहीं तो सभी लोग कमीशन में जायेंगे और कहेंगे कि हमारे इतने दिनों से केस पड़ा हुआ है कोई इंसाफ नहीं होता है। फिर जेल की दशा भी आपको सुधारनी होगी। आप जानते हैं जेल की हालत कितनी खराब है। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जेल में जबर्दस्ती हरिजन को पकड़ कर लाया जाता है। इसलिए कि जेल में स्वीपर नहीं मिलता है। उसको किसी भी दफा में फंसा कर लाया जाता है। इसलिए कहता हूं जेल के लिए भी करना पड़ेगा। जहां पर नक्सलाइट्स हैं वहां पर हमारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए वहां की समस्याओं

[श्री चतुरानन मिश्र]

को देखना पड़ेगा। दूसरे यह कहता हूं कि जो कानून हैं उसमें आपको संशोधन लाना पड़ेगा अगर यह कमीशन बनाते हैं जैसे टाडा है इसके बारे में मैंने प्रधान मंत्री को पत्र भी लिखा था। प्रधान मंत्री से आपसे पास आया था इसलिए आपने जवाब भी भेज दिया है जिसमें कहा है 50 हजार लोग टाडा के अंदर नहीं हैं। आपने कहा है 37 हजार या 17 हजार लोग ही टाडा में है। 17 हजार आदमी, इस देश के नागरिक बिना किसी मुकदमें के दो-दो वर्ष से जेल में पड़े हैं तो यह कौन सा मानव अधिकार आपने दे रखा है। अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि इसके लिए कानूनों में, सिस्टम में, न्याय की पद्दति में उपयुक्त सुधार लायें। मैं इसलिये कह रहा हूं हमारे देश के सामने कठिनाइयां हैं। हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों की देन है। दूसरे हम लोगों के देश में हजारों साल से ब्राह्मणवाद की प्रथा के चलते हरिजन और दूसरे लोगों के साथ भयंकर दुर्व्यवहार होता था। यह हिन्दुत्व का तरीका था। उसका अभी भी अवशेष है। इसलिए इसमें काफी टाइम लग रहा है। लेकिन हम को खुशी है कि देश ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। यहां स्वतंत्रता के बाद जनतंत्र रहा है बिना किसी ब्रेक के। इसलिए मैं समझता हूं हम लोग एक नई दिशा में देश को ले जायें और उसके लिए आप मानव अधिकार के उन कामों को करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. NARREDDY THULASHI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice Chairman, Sir, at the outset I would like to say that this Bill is a face-saving device. There is no doubt about that. Even than I would like to support the Bill. There is a proverb in Telugu, "Guddi Kannu kante mella kannu machidi" It means a squint eye is better than total blindness. That is why I support this Bill.

Sir, the Government is not sincere either in brininging this Bill or in framing this Bill. At present this Bill is being brought only to meet the criticism of Amnesty International, Asia Watch and such other human rights organisations; and to make them silent and to get rid of the headache from these bodies. Amnesty International and other human rights organisations have been continuously publishing and making propagani alleging massive and gross violation < human rights in India, especially i Punjab, Kashmir and some other State Some other countries like Pakistan ai taking advantage from this propagand and are trying to tarnish our image i almost all the international fora. That i what is happening. But in thi propaganda, it is not totally correct. A the same time, it may not be totally false There may be some partial truth in it We have to accept that.

There are two kinds of violations o human rights. One is by terrorists and thi other is by the State Government itself We all know that there is violation o; human rights in our country by terrorists They are killing innocent people, people travelling in buses, people travelling in trains, people working in fields and people attending marriage functions. There is no doubt about that. But the Government can control them by using the laws of the land. They can prevent terrorists from violating human rights. But what about the- violation of human rights by the Government itself not only in Kashmir, not only in Punjab, not only in Assam but everywhere in the country? Everyday, there is violation of human rights by the State machinery. If you go through the newspaper everyday you will find that there a large number of lock up deaths, there are a large number of lock up rapes and lock up atrocities especially on the weaker sections and on women. Everyday we read about these things in the newspaper. These are facts. Moreover, what about TADA and NASA? We all know that there is gross misuse of TADA and NASA. There Acts are used to suppress, to oppress, to harass the political oppoents, trade unions, student movements and so on. There is gross misuse of TADA and NASA. Our Constitution provides some fundamental rights, some human rights under articles 14, 21,39 and 41 of the 'Constitution of India. There is freedom of speech, there is freedom of movement, there is equality before law; there is right

to work and so many things. But the law enforcing authorities are violating these rights. That is why there is a necessity of bringing this Bill. But this Bill is not at all comprehensive. There are many shortcomings and anomalies in this Bill. Number one, the armed forces do not come under the ambit of this Bill. The Government may say that the armed forces are working under different conditions and it is not proper for them to demoralise the armed forces. I agree with that. In fact, they are meant for separate purpose. But are we deploying them for the same purpose for which they are meant? No, everyday we are using the army for other purpose. The State Governments are asking for the deployment of the army in the States. The Central Government is deploying army for each and everything. Even for civil matters, the army is being employed these days. If you deploy the army only for a specified purpose, then it is all right. But if you want to deploy the army for each and everything, then they should also come under the purview of this Bill.

The second thing is only recommendatory and not mandatory.- The Commission comprises many eminent people, important people and prominent people. Do you think that the recommendations of these people have no weight? If you feel that their recommendations have some weight, then why don't you make their recommendations mandatory? That is my second point.

The third point is regarding the constitution of the State Commissions. They are *not* obligatory. The State may or may not constitute it. Again, that is an anomaly. For this Commission, there is no investigating mechanism and there are no penal powers. So, my suggestions are: Number one: Article 27 of the International Convention on Civil and Political Rights shall not be denied in those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist. Persons belonging to such minorities shall not be denied the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion or to use their own language. This is article 27 of the International Convention on-Civil and Political Rights. But there is no provision for this in this Bill. I request the hon. Minister to insert a clause in this Bill with regard to article 27 of the International Convention on Civil and Political Rights.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.NARAYANASAMY): You have taken more time. Kindly conclude.

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Sir, while concluding, I would say that even though this Bill is Tor an eye-wash purpose, even though this Bill is a face saving device, it can create some awareness among the public with regard to fundamental rights, it will create some fear complex in the law enforcing authorities and it will have some impact as a watch-dog on the society. So I support this Bill.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Sir, it is very clear from the manner in which the Ordinance was issued that there are outside presures working on us because the procedure adopted was very unusual and not according to the spirit of the Consitution. I wish the country should have developed such a strength that it can withstand such outside pressures. We should have had the courage to tell this to certain powers who are using these human rights as an instrument of international power politics. What is being done is that this bogey of human riglus is being used to pressurise certain people. I wish our country had the strength to tell them that when these had to face a particular situation in South Mogadishu, they f~ed from the helicopter on unarmed people. I wish our country had the strength to tell them that when there was the so-called violation of Kurds' human rights in Iraq, then a lot of noise was made, but when it happened in Turky, no such noise was made*' So it is a question of fighting the double" standards which are being followed 4n respect of

[Shri Jagmohan] Dhuman rights. And human rights we must understand are part of the human order. They are not existing in isolation. And the hon. Minister, I feel, should pay attention to it. what I was saying is if human rights are part of the human order and if the human order is so-created at international level that 82 per cent of the resources are cornered by a few people and only 18 per cent resources are left for the remaining 82 per cent population, then the human rights are going to be violated one way or the other. Now if a person is drinking polluted water and is dying of pain and suffering every day because of stomachic trouble, I feel this is a much greater violation of human rights than what we are talking about. It is true that our policemen resort to deviations, things which they should not do. But have we ever applied our mind to a question: why is it that we are not able to train our police properly? Because, I know, there are not enough resources. Why is it that 80 per cent of our police-constables staying in Delhi are houseless? And when these people live in this environment, frustration is bound to be there, irritation is bound to be there. And when they live alone, when they live without families then all types of deviant behaviour which we witness is bound to be there. So, this is the first point, I think, we must keep in mind, which we have forgotten.

The second point which we must remember is. If there are false, frivolous and mischievous complaints, motivated complaints, knowingly an intentionally made, then what is the remedy available? I find no provision in this Bill in which the Commission can say that his complaint was frivolous this was mischievous, this was vexatious and the fellow who has made the complaint must be punished. In a normal law if somebody lodges an FIR and gives a false information in the FIR or if he lodges a false FIR, he is liable to prosecution. The aggrived person can lodge a counter-prosecution. I think there must be a provision in the Act that the commission must have the power to make recommendations with regard to .false, frivolous and mischievous complaints. And there are four or five examples which I have in view, and even the courts have declared that these are fabricated documents which were produced. And what will happen in such cases? You will only over-burden the commission with so many complaints that even genuine complaints will not be looked into.

The third point which is very important is, that it is implementation of the existing laws that matters. There is hardly any other court in the world which is so judicially active as our Supreme Court.

On a simple letter the Supreme Court can issue a notice. It can call for files. It can do anything. It has done it in the past. In fact, a number of people have criticised our Supreme Court for being over-active in judicial work because they are taking up functions which do not really belong to them. If the police does not behave properly I have a right to go to the court and make a complaint. I have a right to go to the High Court if my complaint is not properly looked into. So, it is really the implementation of the law that matters and not another agency which you need to create. Because this agency, as it happens, will also depend on the same laws. It will also depend on the same agencies for getting reports. Supposing the Commission has the right, if a state Government which is protecting a particular officer does not want to punish him, The Commission cannot do anything. The Commission cannot do anthing. They will just say, "All rights, we will institute a judicial inquiry." Then they say, "All right, you give a notice to the officer concerned." Because, under the Commission of Enquiry Act you have to give a notice. In Kiran Bedi's case the Supreme Court has held that the commission has got to do it.

Therefore, there will be such procedural wrangles that the Human Rights Commission will never be able to complete any case expeditiously. Even if it is able to complete, it can recommend prosecution.

Supposing with the best of intentions the Central Government says, "All right, we will give sanction for his prosecution"? What can you do? He is a State Government employee. The State Government may or may not prosecute. The state Government will say, "We don't agree." The law vests powers with them. Then you know what happens in the courts. There is a provision that they will have to examine record of evidence. They will have to assess evidence and even if a prosecution is launched, you have to go to the court. The court will follow the current procedure, the same summoning etc. Now, no criminal case is being settled for over five years. What will happen then? So, the very idea, in my view, will lead you nowhere. It will only increase your expenditure. Increasing your expenditure means increasing you incapacity to do the real things, the productive work. Supposing you spend Rs.2 crores on this Human Rights Commission, if you spend this Rs.2 crores to house the poor people, if you give it for providing water supply to the police colonies, if you spend it on creating a good training institute for the police, it would yield much better and positive results.

Another point which I would like to mention is that this Act creats another danger, that is, it will have some adverse influence on the independence of the judiciary. When you are taking ex-judge from among the Chief Justices of the Supreme Court and are fixing the age limit at 70 years, what will happen when he is about to retire? He may be looking for some job. So, this is a ready-made job for chief Justices. I think it needs to be considered. I will only give a hint that the Chief Justices of the High Courts and the Chief Justices of the Supreme Court will now have another avenue to look for a job and other facilities which go with it. The basic point which we most understand is whether this Commission is going to yield the results which we have in view or it will only increase our expenditure and fret and fume and yield very little positive results. I wish our country developed the strength as China has done. At the Seattle Conference without blinking an eve-lid they said, This-human rights-is our business. We know how to protect it. Foreign powers have no right to tell us." Unless the country develops that strength we will fumble from one mistake to the other and we will go on compounding our problem.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। महोदय। यह जानकारी मिली है कि लोक सभा 28 और 29 तारीख को जे०पी०सी० की रिपोर्ट पर विचार करेगी। अगर यह सत्य है तो लीडर आफ दी हाउस से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि राज्य सभा का सेशन भी 28-29 को रख कर जे०पी०सी० की रिपोर्ट पर विचार करवा लें। अगर यह सहमत हों तो चेयरमैन साहब से कहा जा सकता है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, we don't have to follow everything the Lok Sabha does because we are a separate House. But the Deputy Chairman has suggested that she would call a meeting of the leaders of all parties now, maybe, in th next half-an-hour, and take a debision independently of what the other House should do. I don't think it is a proper precedent for us to say that everything that is done in the other House should be done here.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: सवाल यही है जब यह सदन बैठ रहा है और सारी सरकार यहां रहेगी तो यहां भी.. (व्यवधान).. बैठ सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister is replying. Kindly hear the Minister. The

[Shri V. Narayanasamy]

Deputy Chairman will call a meeting and *it* will be decided there.

श्री मार्गरेट आल्वा: यह कोई बिल तो नहीं है कि दोनों हाउसेज को साथ साथ पास करना है हम तो पहले भी बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं ..(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: दो दिन चाहिए, एक दिन में नहीं होगा ..(व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट आल्वा: सब पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स का डिसकशन होने दीजिए .. (व्यवधान)

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I cannot say that the Home Minister's agency has somehow choked my voice. Even then if you kindly permit me, I would like to go two seats ahead.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly come.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): If you like, you can give it in writing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Home Minister, that is not allowed.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: That is a very good ruling.

Mr. Vice-Chairman, the Bill, which is before us has a very good name no doubt, i.e. the National Human Rights Commission and State Human Rights Commissions. Human rights, it seemed from the discussion, are cherished by us all, the Treasury Benches and the Opposition. That is really a good indication. But my one submission would be that the Human Rights Commission should not be a body constituted by the Government because the burden of complaints regarding violation of human rights falls really, most of all, on the constituted authority of the land, *i.e* the Government; I mean the allegations are against the Government. Though they may not be justified in all cases but it is a sort of the price of wisdom in the eyes of the people at large, the police, the military and other agencies. It is not the Ministry which is responsible for all the misdeeds. Nobody suggests that they are responsible for the conduct of the police and the Army. Therefore, I think that the question of the Human Rights Commission has come because it has become a habit of the Governments all over the world, not in India alone, to defend the acts committed by their armed forces or the law and order machinery, In the name of keeping up the morale; for example, even these days the armed forces have not totally been exempted. But what has been suggested may be worse than the exemption. Why? Because they have to function under difficult circumstances. But who do not have to function under difficult circumstances, even the police?

Even yesterdary the question of Manu came up:

Now here the upper castes are violating the human rights of so-called lower castes. This is almost a national phenomenon beginning from Kerala to Kashmir. Then other types of human rights violations are also there. If the Government calls the 'military to discharge the function of the police, the Army*also should be subjected to the same discipline and same penality under which the police functions. This discrimination should not be there.

5.00 P.M

There should not be any discrimination between the army and the police. The army is there in Kashmir and it may definitely be subject to investigation in order to reassure the people of Kashmir. But what I was saying was that the Human Rights Commission should really evolve from the human rights movement as a watchdog body. A point was made out that there are courts. Will there be newer courts or new Government agencies in the Human Rights Commission? Or are the courts which are already overburdened with cases and litigations going to be saddled with this job? There have been suggestions like that. But there is a provision for special

courts, constitution of special courts for the purpose. If the Government does not constitute the Human Rights Commission ----- the Central Government and . the State Governments ---------- in consultation with the highest judiciary, that Commission will not have real authority to protect the Human Rights Commission. I cannot give them all" the credit for bringing it without bringing in the question of Mr. Clinton or the British Government, the Amnesty International or the Asia Watch Organisation. If I accept the word of the Government, if I don't question the *bona fides* of the Government in bringing this Bill, it is not just to silence the foreigners. It is really a step in order to reassure the people of the country that their fundamental rights will not be trampled. Even in that case it should evolve out of a genuine human rights movement and it should not be like in the emergency days when we used to have the *Sarkari Sadhu* who talked of *anushasan.* It should not be a *Sarkari Sadhu* kind of an organisation. A *Sarkari* organisation will not be able to create confidence in the minds of the people. Thank you.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Mr. Vice-Chairman, at the outset I would like to express my thanks to all the hon. Members who have participated in the discussion and supported the Bill. I can quite appreciate the number of suggestions which the hon. Members have given while speaking on the subject. Though they supported the Bill, everyone had some kind of suggestion to offer. At this stage I would say that we just did not have any kind of experience and that is why we thought it necessary that it should be heavily weighed in favour of people who have a judicial background. If you go through the Bill, you will find that the members of the Commission are persons who have had a judicial background. This is a kind of pioneering work that they will be doing. Let them lay down a very good foundation. I can assure the hon. Members that Government is very sincere about the Commission discharging all its functions in letter and spirit and would like to see that the recommendations coming from such a high body are 'normally' accepted by the Government. When I use the word normally, everybody is bound to feel that there can be a number of instances where the recommendations may not be accepted. I can give the example of the Finance Commission. My hon. friend, Mr. Mahajan, wanted the Government to give an assurance that the Government is going to accept the recommendations of the National Human Rights Commission.

Certainly, I don't have any hesitation. In the case of the Finance Commission, it is also a recommendatory body; the recommendations are not mandatory, not binding on the Government. But, at the same time, you will find not even one instance where the recommendations of the Finance Commission have not been accepted by the Government. So, this is just a begining that we are making. And, normally—I am using the word 'normally' because of the fact that the recommendations of all the Commissions which are appointed under the Commissions of Inquiry Act may or may not be accepted, but this being a specially constituted body, I can assure the hon. House that in letter and spirit, we would like to follow what such a high-powered body is going to recommend to the Government and their recommendations are going to have definite value with the Government. The Government is a democratic Government. And if the recommendations of such a high body are being rejected by an elected Government, for that matter, I .don't think that that Government can possibly function in this country. That is the kind of spirit that we would like to have while approaching the recommendations of this Commission.

Sir, there are a number of issues that have been raised. At the very outset, I would like to clarify one thing. I am quite agreeable with what the hon. Member,

[Shri S. B. Chavan]

Shri Jagmohan, has said. There is no denying the fact that there is a total imbalance in the world situation. All the resources are concentrated in a few developed countries and the dictation of the human resource values is supposed to be only the responsibility of all the developing countries. So, this is a kind of ana chronism in which we are. But I can definitely say,—whatever others might say—at least I can convince the House, that this kind of recommendation was made in the Congress manifesto. If you go through the manifesto of the Congress Party, You will find that it was clearly stated that we proposed to constitute a Human Rights Commission. And it is in furtherance of that assurance which we had given to the people at large at the time of elections that this Commission has been constituted. Now, the only point that arises is: What was the necessity of having an Ordinance? I quite see the point. I am sure that hon. Shri Mahajan has gone through my reply in the Lok Sabha and that is why he was trying to point it out; he was anticipating what the line on which I am going to reply is going to be. The point is very clear. We had committed ourselves in May, 1993. The Bill was introduced and it was sent to the Standing Committee. The Standing Committee almost finalised its discussions. Our officers were closely associated with the working of the Standing Committee. A number of witnesses were also taken by this Standing Committee. All the people who are supposed to be human rights activists also could go before the Committee and submit their views. Thereafter, the Committee was on the point of giving its recommendations when, actually, it came to our notice that there were some people who were interested in having a kind of malicious propaganda against India. They were trying to malign our country by bringing some kind of resolution in the U.N. body. I consulted leaders of all the Opposition parties. I don't think that any political party, for that matter, can take the plea that the Government had consulted only a few of them and not all. I have been able to discuss with most of the political parties and the opinion was unanimous that in the national interest, we should bring such kind of Ordinance.

With the rull backing of all political parties, this Ordinance was issued. So, there is no thing hanky-panky about this. It is not because of anybody's pressure. It is in the national interest which we want to preserve and because of this, this kind of Ordinance was thought necessary and that is why it was promulgated. I don't think anybody can possible make a claim that because of some country's opposition or pressure, we have brought forward this kind of a legislation. It is far from the truth. Of course, there are bound to be a large number of international organisations which have now propped up. Unfortunately, for us there have been many so-called human rights activists in our country. Hon. Member Shri Jagmohan has, in fact, referred to this. He said that for the members of the judiciary who will be retiring, this will be given as a kind of enticement.

I think it will be unfair on my part of accept this kind of allegation which he has made. At the same time, for the information of the House, I can say that there are a large number of people who have judicial background, who have retired and who have been vociferously taking interest in human rights activities and there is nothing wrong in taking their guidance. So, I don't think it will be a correct preposition to say that they are going to have this kind of allurement from the Government. On the other hand, they will be serving the country in a better manner by giving all kinds of suggestions. It is asked by someone: Why is it: only the Chief Justice and not the other senior Members of the judiciary? Why did we want the Chief Justice to be the Chairman? I have told you at the very beginning that it is only a beginning. That is why we want to have a firm

foundation being laid by very eminent people who should be able to say that these are the lines on which you should proceed. That is the only point. It does not mean that this is the last word. I can assure the hon. House that there is definite scope for improvement. We can think of amendments depending upon the experience that we will be gaining in this field. So, hon. Members should not feel that since this Commission has been constituted and the Bill has been passed, all our amendments have not been accepted and, so, there is hardly any remedy left. I don't think that thej^e is any scope for such kind of interpretation. Other Members can also be accommodated depending upon the time. When reconstitution of the Commission takes place, if we feel that a wider scope has to be given, at that time we can certainly think of having amendments of the nature indicated by hon. Members.

Another point which was raised by all hon. Members was about reservations of the Chief Justice of India. I must, of course, say beforehand that it was Shri Mahajan who wanted to know what the reservations of the Chief Justice of India were. I don't think I should disclose anything on his behalf. It will not be proper to say for what reasons the Chief Justice thought it necessary to be disassociated. It may be to maintain his independence that he does not want to associate himself in this connection. It is entirely for him. I cannot possibly give any explanation on his behalf. He might be having his own reasons. It is entirely for the Chief Justice of India to consider whether his independence is being compromised or not. This is the only issue on which all the hon. Members wanted to have some information

SHRI PRAMOD MAHAJAN: He might not be having any reasons. He might be having reservations. Having reasons is something different from having reservations.

SHRI S.B. CHAVAN: I don't think there are any other reasons. Still I cannot possibly say anything on his behalf. It is entirely for him.

Another common point which was made by all hon. Members is about the powers of the Commission. Everybody has asked about this. They have said that this is a kind of Commission which has no teeth; this is a Commission which is recommendatory; this is a Commission which has no mandatory powers; what happens if a State-level Commission is not appointed by a State Government because the word 'may' is used, etc. There are two views held by different Members. One view is that because of the word 'may', State Government may not appoint State-level Comissions. Another view expressed is that a State Government might constitute a Commission to stall the proceedings so that the matter did not go before the National Human Rights Commission.

And, Sir, the third dimension which the honourable Members did not consider was what was going to be the relationship between the National Human Rights Commission and the other three Commissions which have been appointed. So, these are the three dimensions. It is absolutely dear and there is no conflict. If the State Governments want, they can definitely do it. But, being in a federal structure, if we have to say that we order them to appoint this Commission, I do not think that it would be in the federal spirit of the Constitution. We should not try to impose anything on the State Governments. It is entirely for the State Governments to. decide about this matter. But why are we considering that we are the only votaries for protecting human rights and for preventing the violation of human rights? Why don't you think that even the State Governments are also interested in it? There was not even one voice of dissent and when we called the meeting of all the Chief Ministers, all were unanimous that such a Commission should be set up though some people did have some kind of a different view also.-But, ultimately, everybody came round

[Shri S.B. Chavan]

and said that there was no reason why we should not constitute such kind of a Commission. If the mater is taken care of by the State Commission, the normal practice will be that the National Human Rights Commission will not duplicate the matter. Both the Commissions should not inquire into the same matter and if they have to differ, then what is going to happen in such a situation? This question also has been visualised. It is totally ruled out. Such a situation will not arise at all. Once the State Human Rights Commission is seized of the matter, the National Human Rights Commission will not take up the same issue for inquiry. So also, in the case of the Chairmen of the other three Commissions who have been appointed, they have been taken as ex *officio*. One is the Chairman of the Minorities Commission, the other is the Chairman of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission and the third is the Chairman of the National Commission for Women. Now, suppose one Commission is inquiring into a matter and it is pending with a Commission, say, with the National Commission for Women. Should the National Commission also go into the same problem? This is a point which has definitely been taken care of and if you go through the provisions, you will see that they are absolutely clear and it is clear that barring the pending cases, in the rest of the matters, the National Commission will have the right to inquire.

SHRI JAGMOHAN: Suppose I want to frustrate the National Commission. All that I have to do is to run faster to the Minorities Commission and make a complaint there.

SHRI S.B. CHAVAN: I am replying to that point. Why should we arrograte to ourselves as if we are the only votaries for the protection of human rights and the State Governments are totally oblivious of the same? At least, so far as the State Governments are concerned, I can assure you that they are also activated by the same intentions as the Central Government is. We should not unnecessarily create any kind of conflict between the thinking of the State Governments and the Central Government.

SHRI JAGMOHAN: It is not only the State Governments, but also the other Commissions. If I want to make a complaint to that Commission, then the National Commission cannot take cognizance of the same thing. .

SHRI S.B. CHAVAN: If they were to start the proceedings, there will be very little work left for the National Commission and I do not think that any of the Commissions which have been constituted is going to start the proceedings with this kind of an intention of stalling any kind of things going to the National Human Rights Commission. This is not the spirit in which these matters have to be looked into. If you have that kind of an experience, maybe we would make the necessary amendments at the appropriate time.

SHRI MENTAY PADMANA-BHAM (Andhra Pradesh): What about the appellate jurisdiction? Some other Members also suggested that some sort of appeal could be there.

SHRI S.B. CHAVAN: In fact, I was going to reply to that because Mr. Madhavan had raised that point.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Some other Members also raised that point and I think all Members are equal here.

SHRI S.B. CHAVAN: All right. First of all, the honourable Members will see that there is no right of appeal on the recommendation.

Is it a judgment on wnich there should be an appeal?

SHRI MENTAY PADMANABHAM: It can be even a recommendation.

SHRI S.B. CHAVAN: I don't think that there is any scope for having any

kind of appeal from the State level Commission to the National Human rights Commission. It will create unnecessary conflict which we should try to avoid. And you must bear in mind that this is, after all, the recommendation of a particular Commission. So, there is no scope for any kind of appeal ....

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Not exactly appeal. Suppose the State Commission, for any reason, makes a recommendation which is not in consonance with the actual truth or if anybody who has gone to the State Commission is aggrieved by that recommendation, he may be allowed to appear before the National Commission. There is nothing wrong. It is not exactly appeal, but it is something like that.

SHRI S.B. CHAVAN: At least we are absolutely clear that there is no such occasion when, in spite of the recommendations of the State Commission, the State Government—as I have stated earlier, any democratic Government for that matter-dare do this. If they were to do that, their future is going to be in jeopardy. You must be careful about it. And any State Government, and for that matter, even the Central Government, which is a duly, democratically elected Government, if they were to go against the wishes of such a high-powered body, I don't think that we can possibly afford such a kind of luxury. So, we have to be careful that all these recommendations, though we see that they are recommendatory, but in spirit, we have to believe as if they are mandatory and not recommendatory only. That is the kind of spirit that is required. Otherwise, we do not want to create this Commission just for having some kind of an eye-wash as some hon. Members said. We are not interested in doing that. We are really interested in finding out where the atrocities are committed and how best we can possibly find solution to such problems. It is not just for having some kind of a Commission that we want to create this Commission.

AN HON. MEMBER: What about the Chairman of the Backward Classes Commission?

SHRI SB. CHAVAN: This was another issue which was raised. I am happy that the Minister of Welfare is present here. According to my information, the Commission which has been constituted for Backward Classes, it is going to decide which are the communities which deserve to be included and which are the communities which are going to be excluded. It is not in that sense that it is a Commission. If a full-fledged Commission for Other Backward Classes is appointed, I can assure the House that the Chairman of that Commission will become a Member of this Commission. So, there is no reservation on that point. We are absolutely clear on that. But the nature of work is totally different from the kind of work that we expect from this Commission.

Sir, one mere point raised was about the Armed Forces. About the Armed Forces and the para-military forces, I must say that if the hon.Members go through the provisions, even under their own martial law regime that they have, they have their own Acts. And under their Acts, they have to maintain the discipline, but at the same time take very stringent action so that there is no indiscipline in the Armed Forces. They themselves are interested, and you will be surprised to know that in Kashmir itself, when a number of allegations were made against the Army, the Army officers themselves said, "we are prepared to submit ourselves before the Press Council of India. Let them enquire into the matter." And the Press Council of India constituted their own body and their recommendations were given to the Press Council of India in which they said, "what was alleged against the Army was found to be totally false." So, this is the kind of spirit that our Armed

[SHRI S.B. CHAVAN] Forces have. Hon. Members have to realise the conditions in which both the Armed Forces and the para-military forces are working. These people have been working in totally 100 per cent adverse conditions. And instead of appreciating their work, if everybody were to express doubts about their bona *fides* and the way they are working, I think, we are doing a great disservice to all those who are prepared to sacrifice their lives for the country. There are a number of people who have sacrificed their lives.

If the-hon. Members are interested, I have with me full information as to how many army officers or naval officers have been given imprisonment for 10 years, for 9 years, for 8 years, and some have even been discharged from service. Number of disciplinary proceedings have also been started against some officers apart from para-military officers where similar kind of action has been taken. Almost 160 officers in the case of J&K and almost 260 persons in the case of Punjab have been given very stringent punishment in order to see that they do not go against the good name earned by their own forces and create a sense of no confidence in the minds of the people. So the forces themselves are very conscious of it and the Government is equally interested in seeing to it. We appreciate that they are working under adverse-circumstances. At the same time we should not allow conditions to be created where they can commit excesses and get away with it. We are certainly not interested in that kind of thing. Even under this Act there is a provision that if there is a heinous crime committed like rape or murder or attempt to murder, it is left to the discretion of the Government whether they should be allowed to proceed under another Act or this Act which should take recourse. It is a matter of discretion with the Government. There have been instances where cases have been referred to ordinary courts and they have taken a decision in the matter. So, it is not the we are not aware of it. But here als there is a special provision which sa> that they will get a report from th Central Government and if they ar satisfied that adequate action has bee taken against the officer who is th culprit, then they may not proceed with i but if they are not satisfied, they can stil recommend to the Government tha adequate punishment which they shouli have been awarded, should be awarded and certainly the Central Governmen will* have to reconsider the whole thing There is a provision for revision also an< that provision can be utilised fo enhancing the punishment or givinj adequate punishment to the officer.

There is one more point which was raised by Shri Chaturanan Mishra. He expressed some kind of a doubt, and thai is about the special human rights court! for which provision is there. There is also a provision that some of the existing courts also be designated as special courts, and might be that, as it is, the courts are over-burdened and if some court is going to be designated as a special court for human rights violations also, then you will be able to get a speedy justice. We shall definitely keep all this in mind and would request the State Governments to see that special courts are being created for this purpose so that speedy disposal of cases is there.

One more point and I have done. And that is about the provision of one year's time limit. Hon. Member, Shri Madhavan wanted that if the victim is able to produce sufficient evidence to snow that he will have to go before the human rights court and satisfy them that there were valid reasons why he could not come within the period of one year, might be, they can condone the same. I can only say that this is a kind of ad hoc sort of thing. One may ask: why one year? Why not 3 years or 5 years? These are all ad hoc provisions. The idea behind the whole thing is, we do not want the Human Rights Commission to carry on the legacy of a huge number of

cases of incidents that took place 2 or 3 years back and all these number of cases are piled up and the whole thing starts with a huge backlog. That should not happen. The Human Rights Commission must have sufficient time at its disposal to look into the cases which occurred very recently. That is why, that provision has been made.

To the extent possible, I have tried to meet the various points which the hon. Members have raised,

SHRI S. MADHAVAN: What about surprise jail visits?

SHRI SB CHAVAN: On the question of surprise jail visits, I would request the hon. Member to consider this point. In the beginning, we had a provision that with the permission of the State Government, they can go and visit. The Standing Committee recommended that it should not be so, the Commission being a high-level body. You must also understand the fact that it is a State subject. We are not informing the jailor We are informing the State Government To allege that the State Government and the jailor may be hand-in-g!ove would be rather too much. I do not think we should create conditions which hamper their legitimate functioning. We cannot also ignore the State Governments. They are just supposed to be informed. They would be informed. The Commission would go there, visit the jail and find out whether any atrocities are being committed on the jailmates.

Sir, these were the points. I once again thank all the hon. Members and I can assure the hon. Members of this House that we would like to implement the recommendations of the Human Rights Commission in the letter and spirit in which they would be submitting their reports. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Mahajan, you can reply, but kindly be brief.

श्री प्रमोद महाजन: उपसभाध्यक्ष जी, प्रारंभ से ही मानवाधिकार आयोग के गठन को सदन ने सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार किया है, व्यवहारिक रूप में जो कठिनाइयां बताई हैं उन के संबंध में गृह मंत्री जी ने कुछ समाधान करने का प्रयास किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक नई प्रक्रिया है और नया प्रयोग है और इस प्रयोग की सफलता की कुछ प्रतीक्षा करें और अगर इस में आगे चलकर हमें कुछ त्रुटियां दिखाई देती है तो उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस चर्चा के उत्तर में मुझे बहुत लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक मुद्दे की ओर गृह मंत्री जी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह सच है कि विकसित देश जो अपने देश में मानवाधिकारों का हनन करते हैं, विकसनशील देशों को अक्ल सिखाने का प्रयास करते हैं, यह जितना गलत है उतना ही यह भी गलत है कि विकसनशील देश यह कहते रहें कि लॉस ऐंजेलस में भी वैसा ही होता है, तुम भी तो करते हो अधिकारों का हनन, यह कहकर एक दूसरे को अक्ल सिखाएं. मैं समझता हूं कि यह भी मानसिकता ठीक नहीं है। हमारी जो न्याय की रचना है जो शायद हमने ब्रिटिशों से ली है, उस का एक मौलिक सिद्धान्त है कि सौ अपराधी भले ही छूट जाएं, एक निरपराधी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था बहुत ही संथ होने के कारण जो कानून पर अमल कर रहे हैं, उन का इस मौलिक सिद्धान्त से विश्वास टूट चुका है। इस लिए हम भी उस सिद्धान्त में विश्वास नहीं कर रहे हैं अपने व्यवहार में कि सौ अपराधी भले ही छूट जाएं, एक निरपराधी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। न्याय इतना संथ होता जा रहा है कि कानून पर अमल करने वाली व्यवस्थाएं दो शस्त्र ले रही हैं, एक तो काले कानून बनाकर न्याय संस्था में जाने से ही रोको और दूसरे सीधे-सीधे आजकल पुलिस बलों में चर्चा है कि कुछ निरपराधी भले ही मारे जाएं, कोई अपराधी नहीं छूटना चाहिए। इसलिए निरपराधी भले ही मरें, अपराधी नहीं छूटना चाहिए यह जो हम दूसरी ओर जा रहे हैं, उसका संथ न्यायपालिका और काला कानून एक कारण है। इसलिए मुझे लगता है कि मानवाधिकार आयोग के केवल गठन से मानवाधिकारों के हनन में कमी नहीं होगी, उसे हम बचा नहीं पाएंगे। हमें देश में फिर से एक मानसिकता खड़ी करनी पड़ेगी, न्यायपालिका में सुधार लाकर उसको गतिमान बनाकर कि वहां न्याय मिलता है, ऐसी हम लाएं तो शायद काले कानून बनाने का प्रशासन को मोह कम हो और न्यायपालिका में जाने से ही पहले रास्ते में न्याय देने का पुलिस बलों को जो मोह होता है, वह मोह भी एनकाउंटर जस्टिस का छूट जाएगा। इसका मौलिक विचार हम न करें तो शायद

[श्री प्रमोद महाजन]

कितने भी गठन हम करते रहें उस गठन के बाद भी हनन होता रहेगा। इसलिए इस मानसिकता का सारे राजनीतिक दल अगर निर्माण कर सकें तो मुझे लगता है उसका उपयोग होगा।

मैं गृह मंत्री जी से फिर प्रार्थना तो नहीं करूंगा क्योंकि वह मानने वाले नहीं है क्योंकि एक वर्ष की समय अवधि जो उन्होंने कही है वह मुझे समझ नहीं आती लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण आश्वासन सदन को दिया है कि इस आयोग की जो भी सिफारिशें होंगी वह सामायतः सरकार स्वीकार करेगी, उसको सम्मान देगी। उनके इस आश्वासन को देखते हुए मैंने जो अपना परिनियत संकल्प रखा था सदन से अनुमति चाहूंगा कि वह संकल्प को विदड्रा करने की इजाजत दे।

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now I shall put the motion moved by Shri S.B. Chavan to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the constitution of a National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions in States and Human Rights Courts for better protection of human rights and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration." *The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now we will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

SHRI S. MADHAVAN: I am satisfied with the assurance given by the hon. Minister. I do not move any of my amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We now take up clause-by-clause consideration.

Clauses 2 to 43 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion w adopted.

THE JUTE MANUFACTURE DEVELOPMENT COUNCI (AMENDMENT) BILL, 1993

THE MINISTER OF STATE IN THi MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLK GRIEVANCES AND PENSIONS ANI THE MINISTER OF STATE IN THI MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, I move:

"That the Bill to amend the Jut Manufactures Development Counci Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken intc consideration."

Sir, the Jute Manufactures Development council set up under the Jute Manufactures Development Council Act, 1983, was following the jute year for its accounting purposes. The jute year is from July to June of the following year. In view of the difficulties that arose out of the differences in the accounting year for the Jute Manufactures Development Council and-the Government of India, it is considered necessary that the Council should also follow the same year for accounting purposes as the Government of India. The proposed Bill seeks to modify the definition of year given in section 2(f) of the Jute Manufactures Development Council Act, 1983 to mean financial year.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I think it is a small amendment and the House can get it passed without any discussion.

SHRIMATI MARGARET ALVA: It was agreed in the Business Advisory Committee also that there will be no discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I think it was